साप्ताहिक
# शांति मिशन
नई दिल्ली

वर्ष-28 अंक- 05 30 जनवरी - 06 फरवरी 2021 पृष्ठ 12

अन्दर पढ़िए

उपभोक्ता संरक्षण की चुनौती
पृष्ठ-6

मिलावट का घातक रोग
पृष्ठ-7

# धर्म के नाम पर
## हिन्दू, मुस्लिम और ईसाइयों में
# भेदभाव
## क्या यही है संघ की देशभक्ति

### आर॰एस॰एस॰ जैसे-जैसे मज़बूत होता जा रहा है वह देशभक्ति को धर्म से जोड़ने के प्रयास तेज़ करता जा रहा है

एक ओर आरएसएस, गांधी जी के प्रति सम्मान का भाव रखने का नाटक करता है वहीं उसके प्रचारक और चिंतक और उससे जुड़े संगठन खुलेआम नाथूराम गोडसे का महिमामंडन कर रहे हैं। पिछली गांधी जयंती पर बड़ी संख्या में हिन्दुओं ने गोडसे की प्रशंसा करते हुए टवीट किये। साफ है कि आरएसएस के कई चेहरे और मुखौटे हैं। वो एक ही समय में गांधी जी के प्रति श्रद्धा भी व्यक्त करता है और उस सोच को बढ़ावा भी दे सकता है जिसके कारण बापू की जान गई।

पिछले कुछ सालों से 'देशद्रोही' शब्द काफी इस्तेमाल हो रहा है। देशद्रोही की परिभाषा बहुत स्पष्ट और सीधी साधी है। जो भी आरएसएस या उसके कुनबे का आलोचक हैं, वह देशद्रोही है। आरएसएस हिन्दू राष्ट्रवाद की विचार धारा का स्रोत है और जैसे-जैसे वह ताक़तवर होता जा रहा है, वैसे वैसे धर्म को देशभक्ति से जोड़ने के उसके प्रयास तेज़ होते जा रहे हैं। वह हिन्दुओं को देश के प्रति वफादार मानता है और बताता है कि कभी प्रत्यक्ष तो कभी परोक्ष तरीक़े से यह साबित करना चाहता है कि मुसलमान, पाकिस्तान के प्रति वफादार हैं। अभी हाल में संघ के मुखिया मोहन भागवत ने फरमाया कि अपने धर्म के कारण हिन्दू स्वभावत: देशभक्त होते हैं। गांधीजी द्वारा कहे गए एक वाक्य को तोड़-मरोड़कर, भागवत ने यह साबित करने का प्रयास भी किया कि गांधी जी की देशभक्ति के मूल में उनका हिन्दू होना था।' सभी भारतीय अपनी मातृभूमि की पूजा करते हैं परंतु गांधीजी ने कहा था कि अगर आप हिन्दू हैं तो आप देशभक्त होंगे ही। एक हिन्दू अचेत हो सकता है जिसे जागृत करना होगा, लेकिन कोई हिन्दू भारतविरोधी नहीं हो सकता' उन्होंने कहा।

इस वक्तव्य के निहितार्थ को समझने से पहले हम यह जान लें कि आरएसएस के शुरुआती चिंतकों में से एक, एमएस गोलवलकर ने खुलकर नाजियों की तारीफ की थी और यह भी कहा था कि मुसलमानों और इसाइयों (जो संघ के अनुसार विदेशी धर्मों को मानने वाले हैं) के साथ वही किया जाना चाहिए जो नाजियों ने यहूदियों के साथ किया था। पिछले कुछ दशकों में आरएसएस की ताक़त में ज़बरदस्त वृद्धि हुई है। उसके विशाल कुनबे में शामिल कई संगठनों जैसे भाजपा, विश्व हिंदू परिषद्, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् और वनवासी कल्याण आश्रम के प्रभाव क्षेत्र का विस्तार हुआ है और उसने राज्य के विभिन्न अंगों, मीडिया और शैक्षणिक संस्थाओं में गहरी पैठ बना ली है। उसकी विचारधारा और सोच अब भी वही है परंतु अब वह थोड़े दबे छुपे ढंग से अपनी बातें कहता है। एमएस गोलवलकर की पुस्तक 'वी ऑर अवर नेशनहुड डिफाइंड' अब भी उसकी पथप्रदर्शक है परंतु अब वह उन्हीं बातों को गोल घुमाकर कहता है जिससे कई लोग भ्रमित हो जाते हैं। जहां तक गांधीजी का प्रश्न है, उनके लिए धर्म एक निहायत व्यक्तिगत मामला था। वे स्वयं को सनातनी हिन्दू कहते थे, परंतु उनका हिन्दू धर्म उदार और समावेशी थी। उनके धर्म का सम्बन्ध कर्मकांडों से कम और नैतिक मूल्यों से ज़्यादा था। सभी धर्म उनकी आध्यात्मिक शक्ति के स्रोत थे। 'मैं अपने आप को उतना ही अच्छा ईसाई और पारसी भी मानता हूं।' (हरिजन, मई 25, 1947)। उनका हिन्दू धर्म आस्था और आचरण दोनों स्तरों पर दूसरे धर्मों का सम्मान करता था और उन्हें अपना मानता था। उनका हिन्दू धर्म आरएसएस के संकीर्ण हिन्दू धर्म के एकदम विपरीत था। संघ केवल विभिन्न मुद्दे उठाकर अन्य धर्मों के लोगों को डराने और नीचा दिखाने में विश्वास रखता है।

**देशभक्ति का सम्बन्ध राष्ट्रीयता से है और राष्ट्रीयता का धर्म से कोई लेना-देना नहीं है। गांधी जी धर्म शब्द का इस्तेमाल दो अर्थों में करते थे। एक तो उस अर्थ में जिसमें आम लोग उसे समझते हैं, अर्थात् आस्था, प्रथाएं, पहचान इत्यादि। और दूसरा, धार्मिक शिक्षाओं में निहित नैतिक मूल्य। वे मानते थे कि नैतिकता सभी धर्मों की आत्मा है।**

चूंकि गांधीजी का हिन्दू धर्म उदार और समावेशी था इसलिए ही वे ब्रिटिश सरकार के ख़िलाफ़ आंदोलन में सभी धर्मों के लोगों के सर्वमान्य नेता बन सके। वेधर्म को न तो राष्ट्रीयता से जोड़ते थे और न ही देशभक्ति से। दरअसल, अपने देश और उसके लोगों के प्रति प्रेम और देशभक्ति की भावना का धर्म से कोई सम्बन्ध नहीं है। देशभक्ति का सम्बन्ध राष्ट्रीयता से है और राष्ट्रीयता का धर्म से कोई लेना-देना नहीं है। गांधी जी धर्म शब्द का इस्तेमाल दो अर्थों में करते थे। एक तो उस अर्थ में जिसमें आम लोग उसे समझते हैं, अर्थात् आस्था, प्रथाएं, पहचान इत्यादि। और दूसरा, धार्मिक शिक्षाओं में निहित नैतिक मूल्य। वे मानते थे कि नैतिकता सभी धर्मों की आत्मा है। इसके विपरीत, आरएसएस जैसे संगठन और मुस्लिम सम्प्रदायवादी (मुस्लिम लीग इत्यादि), धर्म शब्द का प्रयोग केवल बाहरी चीजों जैसे अनुष्ठानों, कर्मकांडों, तीर्थस्थलों आदि के संदर्भ में करते हैं जो चिंतक और लेखक हिन्दू राष्ट्रवाद में यकीन रखते हैं और आरएसएस की सोच से सहमत हैं, वे दिन-रात इस जुगत में लगे रहते हैं कि किसी प्रकार गांधीजी और अन्य राष्ट्रीय नायकों के भाषणों, वक्तव्यों और लेखन से ऐसे शब्द, ऐसे वाक्य खोज निकाले जाएं जिनसे यह साबित किया जा सके कि भारतीय राष्ट्र के उन निर्माताओं की सोच वही थी जो आरएसएस की है। वे अपनी विचारधारा से चिपके रहना चाहते हैं परंतु इसके साथ ही समाज में अधिक स्वीकार्यता प्राप्त करने के लिए यह दिखाना चाहते हैं कि भारत के स्वाधीनता संग्राम के महानायकों के विचार उनके जैसे थे। इसी कवायद के अंतर्गत यह कहा जा रहा है कि हिन्दू 'प्राकृतिक देशभक्त' हैं और देशद्रोही हो ही नहीं सकते। वे यह संदेश भी देना चाहते हैं कि अन्य धर्मों के लोगों का राष्ट्रवाद और देशभक्ति संदेह के घेरे में हैं और अन्य धर्मावलम्बियों को उन लोगों से देशभक्ति का प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा जिनका देशभक्ति और राष्ट्रवाद पर एकाधिकार है और जो हिन्दुओं का प्रतिनिधि होने का दावा करते हैं। ज़ाहिर है यह सोच आधुनिक भारत के निर्माण में मुसलमानों और इसाईयों की भूमिका को कोई महत्व ही नहीं देती। हम उन करोड़ों मुसलमानों को किस खांचे में रखें जिन्होंने ख़ान अब्दुल गफ़्फ़ार ख़ान और मौलाना आज़ाद के नेतृत्व न केवल ब्रिटिश सरकार से लोहा लिया वरन भारत के विभाजन का भी डटकर विरोध किया? हम शिबली, नोमानी, हसरत नोमानी और अशफाकउल्लाह ख़ान का क्या करें? हम अल्लाह बख़्श के बारे में में क्या कहें जिन्होंने मुसलमानों का एक बड़ा जलसा आयोजित कर मुहम्मद अली जिन्ना की पाकिस्तान की मांग का विरोध

बाक़ी पेज 11 पर

# आर्मेनिया अज़रबैजान युद्ध की सीख

आर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच अक्तूबर-नवंबर 2020 में केवल छह सप्ताह चले युद्ध में कुछ ऐसी बातें भी थीं, जिनसे भारत बहुत कुछ सीख सकता है। नगीर्नो काराबाख से जुड़े चिरकालिक विवाद को लेकर आर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच जो आकस्मिक युद्ध हुआ, अमेरिका और यूरोप ने शुरू में उसे गंभीरता से नहीं लिया। भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर को लेकर अक्सर होने वाली झड़पों की तरह ही इसे दो छुटभैयों के बीच की आपसी चखचख माना गया। किन्तु इस संक्षिप्त युद्ध में आर्मेनिया की भारी हार और हार के रणनीतिक व तकनीकी कारणों के बारे में मिल रही जानकारियों से अब पश्चिमी जगत भी सन्न है। अमेरिकी नेतृत्व वाले 30 देशों के 'उत्तर अटलांटिक सधि संगठन' (नाटो) के मुख्यालय में इन जानकारियों को पिछले दिनों गहन अध्ययन किया गया।

विचार-विमर्श का एक ऐसा ही दौर दिसंबर के आरंभ में, बर्लिन में जर्मनी के रक्षा मंत्रालय में भी हुआ, उसमें इंटरनेट पर गोपनीयता बनाये रखने की इन्क्रिप्शन विधि के द्वारा अमेरिका के तकनीकी विशेषज्ञों ने भी ऑनलाइन भाग लिया। बैठकें गोपनीय थीं, इसलिए मीडिया को कुछ नहीं बताया गया। जर्मन रक्षा मंत्रालय के निचले स्तर के एक अधिकारी ने अपना नाम गुप्त रखने की शर्त पर, कुछ पत्रकारों से इतना ही कहा कि 'यदि हम अब तक की तरह ही करते रहे, तो सब कुछ खो बैठेंगे।' कहने की आवश्यकता नहीं कि इस युद्ध ने नाटों की दशकों से चल रही रही रणनीति, सामरिक तैयारी और उसके अस्त्र-शस्त्र भंडारों की भावी उपयोगिता के प्रति संदेह पैदा कर दिया है। नाटो चकित है कि विशाल तोपों-टैंकों जैसे भारी भरकम हथियार भी आकाश में उड़ते मानवहीन स्वचालित ड्रोनों की मार के आगे बेकार साबित हो सकते हैं। उसके सैन्य विशेषज्ञ इस युद्ध को अब दुनिया का पहला 'ड्रोन युद्ध' बताने लगे हैं। आर्मेनियाई सेना वास्तव में एक ऐसी अनुशासित और सुगठित सेना मानी जाती थी, जिसके पास बड़ी संख्या में बहुत अच्छे टैंक और वाहन थे लेकिन तेल की आय से अजरबैजान ने इस बीच तुर्की और इस्राईल से कई प्रकार के बहुत सारे ड्रोन खरीदे हैं। चालकरहित इन ड्रोनों ने अपने हवाई हमलों द्वारा आर्मेनियाई तोपों, टैंकों और सैन्य वाहनों की ध ज्जियां उड़ा दीं। अजरबैजान ने आर्मेनिया तोपों टैंकों और सैन्य वाहनों की धज्जियां उड़ा दीं।

अज़रबैजान ने आर्मेनिया के संभवत: 175 टैंक ध्वस्त कर दिए। उसका साथ दे रहे तुर्की ने अपने कई एफ-16 युद्ध विमान अजरबैजान में तैनात कर रखे थे। दूसरी ओर आर्मेनिया को कुछ ही महीने पहले रूस से आठ सुखोई-30 युद्धक विमान मिले थे। किन्तु वह इन विमानों का ड्रोनो या एफ-16 युद्धक विमानों के विरुद्ध उपयोग कर ही नहीं पाया, क्योंकि रूस नहीं चाहता था कि उसके विमानों और अजरबैजान को तुर्की से मिले अमेरिकी एफ-16 विमानों का कोई सीधा आमना सामना हो।

रूस ने हवाई हमलों से बचाव के लिए आर्मेनिया को जो साजो सामान और मिसाईलें दी थी, वे भी 1980 के दशक के थे। उनके इलेक्ट्रॉनिक सेंसर अधिक ऊंचाई पर तेजगति के विमान को पहचान कर मार गिराने की क्षमता तो रखते हैं पर कम ऊंचाई पर मंडराते धीमी गति के ड्रोनों इत्यादि को पहचान नहीं पाते। आर्मेनिया के पास ऐसा कोई 'जैमर' भी नहीं था, जो उसके आकाश में उड़ते ड्रोनों और अजरबैजान से उन्हें निर्देशित कर रहे केन्द्रों के बीच इलेक्ट्रॉनिक संवाद के सिग्नलों को जाम कर सकता।

अज़रबैजान 'लाइटरिंग ड्रोन' कहलाने वाले बिल्कुल नए इस्राईली ड्रोन-अस्त्र भी इस्तेमाल कर रहा था, जो बहुत छोटे होते हैं। वे किसी पक्षी की तरह मंदगति से हवा में मंडराते हुए बिना किसी बाहरी निर्देश के अपना लक्ष्य स्वयं ही पहचान कर उस पर टूट पड़ते हैं और विस्फोट से उसे नष्ट कर देते हैं। इसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा स्वचालित युद्ध की दिशा में पहला क़दम भी कहा जा सकता है। भारत में लद्दाख जैसे दुर्गम मोर्चो के लिए उन्हें बहुत ही उपयोगी माना जा सकता है।

आर्मेनिया-अजरबैजान युद्ध से जो नई सीखे मिलती हैं, विशेषज्ञों के अनुसार वे हैं - मानवरहित ड्रोनों के जमाने में तोप, टैंक और बख्तरबंद वाहन युद्ध नहीं जीता पाएंगे, जमीनी हथियारों की मारक शक्ति और ड्रोनों की बहुपक्षीय उपयोगिता को आपस में पिरोना होगा, हवाई हमलों से बचाव में इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग प्रणालियों को भी शामिल करना होगा, युद्ध का स्तर ऐसा रखना होगा कि शत्रुपक्ष अंधाधुंध अति पर न उतर आए, अपनी रणनीति में प्राकृतिक भूसंरचना की भूमिका का भविष्य में भी ध्यान रखना होगा।

भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि वह ड्रोनों के निर्माण में अपने मित्र इस्राईल की आश्चर्यजनक दक्षता का लाभ उठाते हुए उससे जल्दी ही न केवल उच्च कोटि के ड्रोन प्राप्त करें, बल्कि उनके स्वदेशी निर्माण की भी अतिशीघ्र चिंता करें। जम्मू कश्मीर और लद्दाख की भूसंरचना आर्मेनिया अज़रबैजान के पहाड़ों से बहुत भिन्न नहीं है। चीन और पाकिस्तान के साथ युद्ध की यदि नौबत आई, तो वहीं आएगी। नवीनतम समाचार भी यही है कि भारतीय सेना इस्राईल से 'लाइटरिंग ड्रोन' सहित कई प्रकार के ड्रोन प्राप्त करना चाहता है। ❑❑

**रूस ने हवाई हमलों से बचाव के लिए आर्मेनिया को जो साजो सामान और मिसाईलें दी थी, वे भी 1980 के दशक के थे। उनके इलेक्ट्रॉनिक सेंसर अधिक ऊंचाई पर तेजगति के विमान को पहचान कर मार गिराने की क्षमता तो रखते हैं पर कम ऊंचाई पर मंडराते धीमी गति के ड्रोनों इत्यादि को पहचान नहीं पाते। आर्मेनिया के पास ऐसा कोई 'जैमर' भी नहीं था, जो उसके आकाश में उड़ते ड्रोनों और अजरबैजान से उन्हें निर्देशित कर रहे केन्द्रों के बीच इलेक्ट्रॉनिक संवाद के सिग्नलों को जाम कर सकता।**



# राशन वितरण पर रहेगी सरकार की कड़ी नज़र

दिल्ली सरकार के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने ई-पॉस के लिए केन्द्रीयकृत निगरानी सिस्टम यानि आधार बेस्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आधारित पोर्टल की शुरूआत कर दी है। इसके ज़रिए विभाग के आईटी विभाग द्वारा हर समय राशन वितरण पर नज़र रखी जा सकेगी। वहीं, राजधानी में कितना राशन बंट चुका है और राशन की दुकानें खुली हैं या बंद इसकी भी जानकारी इस पोर्टल के ज़रिए मिल पाएगी। मार्च में दिल्ली सरकार राशन की डोर स्टेप डिलीवरी शुरू करेगी, जिससे पहले सरकार ने यह पोर्टल शुरू किया है।

ई-पॉस मशीनों को कोटाधारक ऑन करेंगे इस पोर्टल पर पूरी दिल्ली में कितनी दुकानें सक्रिय हैं इसका डाटा आने लग जाएगा। इसके अलावा कितने कार्डधारियों ने पोर्टेबिलिटी के तहत राशन लिया, कुल कितने कार्डधारियों को लिंक किया गया है, कितने राशन कार्डधारियों को राशन वितरित किया जा चुका है, कुल कितनी राशन की दुकानें पोर्टल से जुड़ी हुई हैं और महीने में राशन वितरण का प्रतिशत कितना है इसकी पूरी जानकारी इस पोर्टल पर विभाग द्वारा दी जाएगी। पोर्टल पर दिल्ली के लोगों ने पोर्टेबिलिटी भी शुरू कर दी है। हालांकि, पता पोर्ट कराने वालों ने अभी तक राशन नहीं लिया हैं पोटेबिलिटी व्यवस्था की शुरूआती दिनों में सैकड़ों लोगों ने अपना पता बदलवाया है। विभाग द्वारा पोर्टल पर जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार अभी तक एक भी राशन कार्डधारी ने पोर्टेबिलिटी के तहत राशन प्राप्त नहीं किया है। दरअसल भविष्य में राशनकार्डधारी अपनी नज़दीकी किसी भी राशन की दुकान से राशन प्राप्त कर पाएंगे। अभी तक जिन राशन की दुकानों पर कार्ड को चिह्नित किया जाता है सिर्फ उसी से कार्डध ारी राशन प्राप्त करते हैं।

# राजधानी : सूख रहीं बावलियां, एएसआई ने जल बोर्ड से मांगी मदद

राजधानी की बावलियां सूख रही हैं, जिनमें कुछ पानी बचा है वह भी पिछले सालों में कम हो रहा है। इससे चिंतित भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआइ) ने दिल्ली जल बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को पत्र लिखा हैं इसमें सूख चुकीं बावलियां में पानी लाने के साथ साथ जिन बावलियों में पानी है, उसे बढ़ाने के बारे में सुझाव और मदद देने का अनुरोध किया गया है। कनॉट प्लेस स्थित अग्रसेन की बावली आठ साल पहले सूख चुकी है। यह बावली मैट्रो की भूमिगत परियोजना के निर्माण के कार्य के दौरान सूख गई थी। इसके बाद इस बावली में पानी लाने के लिए 17 सीढ़ियों तक मिट्टी निकाली गई थी, मगर पानी काा स्रोत नहीं मिला। इसके बाद इसी तरह भूमिगत मैट्रो के कार्य के दौरान लालकि़ला की बावली भी सूख गई थी। तुगलकाबाद स्थिति दो बावलियां सालों से सूखी पड़ी हैं।

**पीर की बावली**

इस बावली को फिरोज़शाह तुगलक के समय 1351-88 में बनवाया गया था ऐसी मान्यता है कि यह बावली उस समय चमत्कारिक फक़ीर संत के लिए बनवाई गई थी। यह बावली हिन्दूराव अस्पताल परिसर के एक कोने में स्थित हैं इस बावली में भी पानी सूख गया है।

**बावली-कोटला फिरोज़शाह**

इस बावली को भी फिरोज़शाह तुगलक के समय 1351-88 में बनवाया गया था। यह बावली किला के अंतर है। यह बावली गोलाई में बनी हुई इसमें पानी है, मगर पानी कम होता जा रहा है।

**गंधक की बावली**

यह बावली महरौली के आर्कियो लॉजिकल पार्क में स्थित है। इस बावली के पानी में गंधक के पानी जैसी गंध आती है। इसे इल्तुमिश के शासन काल में 1211-36 के दौरान बनवाया गया था।

**राजो की बावली**

महरौली स्थित राजों की बावली के बारे में कहा जाता है कि कुतुब मीनार की नींव रखने वाले कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद इल्तुमिश ने अपनी बेटी रज़िया के लए इस शाही बावली को बनवाया था। इस बावली में पानी काफी नीचे पहुंच गया है।

**निज़ामुद्दीन दरगाह की बावली**

धार्मिक आस्था की प्रतीक इस बावली में कुछ साल पहले तक गंदा पानी बहाया जाता था। मगर आखा खां ट्रस्ट के मेहनत से झुग्गियों को हटवाया, बावली का संरक्षण कराया। बावली का स्रोत खेल गया हैं अगर अब इस बावली में बहुत पानी नहीं है, कहा जाता है कि इस बावली को निज़ामुद्दीन औलिया ने बनवाया था। ❑❑

संपादकीय

# शांति मिशन

## अमरीका में

# लोकतंत्र जीता, ट्रम्प हारा रस्सी जल गई पर बल न गया

अमरीका के इतिहास में डोनाल्ड ट्रम्प (रिपब्लिकन) संभवत: सर्वाधिक विवादास्पद राष्ट्रपति सिद्ध हुई हैं जिन पर शुरू से ही भ्रामक बयानबाज़ी करने, उल्टे-सीधे निर्णय लेने व वायदों से मुकरने के आरोप लगते रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र के साथ ट्रम्प के 'अच्छे' सम्बन्ध होने के कारण भारत को उनसे काफी उम्मीदें थीं पर ट्रम्प ने उनका भ्रम जल्दी ही दूर करके गत वर्ष अप्रैल में अमरीका में रोज़गार आधारित एच-1 बी वीजा तथा अन्य अस्थायी कामकाजी वीजा 31, दिसम्बर, 2020 तक निलंबित कर दिए।

जाते-जाते ट्रम्प ने इन प्रतिबंधों की अवधि 31 मार्च, 2021 तक बढ़ा कर भारत को एक और झटका दिया। ट्रम्प के दोहरे आचरण के कारण ही अमरीका में रहने वाले लगभग 90 प्रतिशत भारतीयों ने उनके विरुद्ध मतदान करके 'जो बाइडेन' (डेमोक्रेट) की जीत में बड़ी भूमिका निभाई। डोनाल्ड ट्रम्प 1991 और 2009 के बीच अपने 'होटल तथा कैसिनो व्यवसाय' को 6 बार दीवालिया घोषित करने के बावजूद इन पर अपना कब्ज़ा क़ायम रखने में सफल हो चुके हैं और उनका कहना था कि ''मैं चुनावों में भी इसी तरह 'टोटल विक्ट्री' प्राप्त करूंगा।'' उन्होंने तो यहां तक कह दिया था कि वह 20 जनवरी को 'व्हाइट हाऊस' भी नहीं छोड़ेंगे। गत 04 जनवरी को उनका एक ऑडियो भी वायरल हुआ जिसमें उन्होंने जार्जिया के शीर्ष चुनाव अधिकारी को फोन करके नतीजा बदलने का दबाव डालते हुए कहा था कि 'मेरी हार को जीत में बदलने के लिए पर्याप्त वोटों का जुगाड़ करो।'' उन्होंने 03 नवम्बर 2020 को घोषित चुनावों के परिणामों में अपनी पराज्य को अंतिम समय तक स्वीकार नहीं किया और वह अमरीका के ऐसे एकमात्र राष्ट्रपति सिद्ध हुए हैं जिनके विवादास्पद कृत्यों के कारण उनके विरुद्ध एक कार्यकाल में ही 02 बार महाभियोग के प्रस्ताव लाए गए। सत्ता के दुरुपयोग के आरोप में पहला महाभियोग प्रस्ताव 18 दिसम्बर, 2019 को और दूसरा महाभियोग प्रस्ताव 14 जनवरी 2021 को 'हाउस ऑफ रिप्रैजेंटेटिव्स' में पारित किया गया। हालांकि इन दोनों ही महाभियोग प्रस्तावों में आगे की कार्रवाई लम्बित है।

अमरीका के इतिहास में पहली बार ट्रम्प की उकसाहट पर 6 जनवरी 2021 को ट्रम्प के समर्थकों ने अमरीका की संसद 'कैपिटल हिल' पर हमला करके भारी हिंसा की और खिड़कियों के शीशे तथा दरवाज़े तक तोड़ दिए। ट्रम्प के इस कृत्य के विरुद्ध उनकी अपनी ही 'रिपब्लिकन पार्टी' के 10 सांसदों ने भी ट्रम्प के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया और ट्रम्प का साथ देने पर शर्मिन्दगी तक ज़ाहिर की।

बाइडेन के शपथ ग्रहण समारोह में तीन पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन (डेमोक्रेटिक), जार्ज बुश जूनियर (रिपब्लिकन) और बराक ओबामा (डेमोक्रेटिक) ने अपनी पत्नियों सहित शामिल होकर अपनी सद्भावना का परिचय दिया परंतु ट्रम्प ने इसमें भाग न लेकर अपनी मानसिक संकीर्णता का ही परिचय दिया। भारत व अमेरिका दो सबसे बड़ लोकतांत्रिक देश हैं जिनमें लोकतंत्र के प्रति समान रूप से अत्याधिक आदर का भाव रहा है परंतु इस बार अमरीका के चुनावों में ट्रम्प (रिपब्लिकन) व उनके समर्थकों ने जो कुछ किया उससे अमरीका में लोकतंत्र के दाग़दार होने का ख़तरा पैदा हो गया था।

यह आशंका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति 'जो बाइडेन' ने अपने भाषण में लोकतंत्र की रक्षा करने, वैश्विक सहयोगियों के साथ संबंध सुधारने, सच्चाई की रक्षा करने और झूठ को हराने का संकल्प व्यक्त करके और ट्रम्प के मनमाने फैसले रद्द करने के अपने मिशन की घोषणा करके दूर कर दी है। इनमें कुछ मुस्लिम बहुल आबादी वाले देशों पर लगाया ट्रैवल बैन समाप्त करना, विश्व स्वास्थ्य संगठन से समझौता करना, पर्यावरण संधि से फिर जुड़ना, छात्रों को दिए गए ऋणों पर ब्याज़ की वसूली का आदेश रद्द करना आदि शामिल हैं।

लोकतंत्र के प्रति अपनी आस्था का परिचय उन्होंने अपने शपथ ग्रहण भाषण में यह कह कर दिया है कि ''यह किसी व्यक्ति की विजय का नहीं, बल्कि लोकतंत्र की विजय का जश्न है।'' इसके साथ ही 'जो बाइडेन' ने अपने कार्यकाल के प्रथम 100 दिनों में 10 करोड़ अमरीकियों को कोरोना का टीका लगवाने, मास्क पहनना अनिवार्य करने, अमरीकी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने, नस्ली भेदभाव समाप्त करने, आव्रजन क़ानूनों में ढील देने की बात कह कर, आतंकवाद पर चीन और पाकिस्तान को चेतावनी देकर और चीन के विरुद्ध भारत का साथ देने की बात कहकर अपनी सद्भावना का संकेत दे दिया है। दूसरी ओर 'रस्सी जल गई पर बल न गया' वाली कहावत चरितार्थ करते हुए ट्रम्प ने जाते-जाते अपने समधी सहित 143 लोगों को विभिन्न अपराधों में क्षमादान देकर या उनकी सज़ा कम करके, अपनी नई राजनीतिक पार्टी बनाने, जल्द ही नए स्वरूप में लौटने की बात कह कर अपने भविष्य के इरादे भी ज़ाहिर कर दिए हैं।

## तारीख़े इस्लाम

# ख़ुतबाते सीरते तैयिबा

मुफ़्ती मुहम्मद सलमान मंसूरपुरी क़िस्त- 59

### सफ़र हिजरते मदीना

उधर पैग़म्बर अ़लैहिस्सलाम को हुक्म हो गया कि अब आप को हिजरत फ़रमानी है, चुनान्चे आप भरी दोपहर में हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ि अल्लाहु अ़न्हु (जो आप के सब से मुख़्लिस सब से ज़्यादा क़रीबी, सब से ज़्यादा बा ऐतिमाद रफ़ीक़ थे) के घर तशरीफ़ लाए। हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ि अल्लाहु अ़न्हु को अंदाज़ा हो गया कि कोई ग़ैर मामूली बात है, वरना भरी दोपहर में आने का क्या मतलब है? अर्ज़ किया या रसूलल्लाह! क्या हुक्म है? आप ने फ़रमाया कि अल्लाह तआ़ला की जानिब से हिजरत का हुक्म हो गया है, अ़र्ज़ किया या रसूलल्लाह! साथी कौन रहेगा? हुक्म हुआ कि तुम साथ रहोगे? बस फिर क्या था, गोया मुसर्रत और ख़ुशी के मारे आँसू निकल आए, इस से बड़ी सआ़दत क्या हो सकती है कि पैग़म्बर हिजरत करे और एक उम्मती को आप का रफ़ीक़े सफ़र बनने की सआ़दत हासिल हो। अ़र्ज़ किया या रसूलल्लाह! मेरी सवारी हाज़िर है, आप क़ुबूल फ़रमायें, आप ने फ़रमाया कि क़ुबूल है, लेकिन क़ीमत अदा करूंगा, और एक ऐसे शख़्स को रहबरी के लिए तय किया गया, जो उस वक़्त इस्लाम नहीं लाया था, ''अब्दुल्लाह बिन उरैक़ीत'' उसका नाम था, लेकिन रास्तों से बहुत वाक़िफ़ था, उसको किराये पर तय किया गया कि तुम को हमें ग़ैर मारूफ़ रास्ते से मदीना मुनव्वरा पहुंचाना है, और दो ऊँटनी उसके हवाले कर दी गईं कि तीन दिन के बाद ग़ारे सौर के क़रीब ले आना। हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ि अल्लाहु अ़न्हु की दोनों साहिब ज़ादियों (हज़रत आयशा और हज़रत असमा रज़ि अल्लाहु अ़न्हुमा) ने मुबारक सफ़र के लिए ज़ादे सफ़र तैयार किया। हज़रत असमा फ़रमाती हैं कि थैला बाँधा जा रहा था, लेकिन बाँधने के लिए रस्सी नहीं मिल रही थी, तो मैंने अपना इज़ार बंद फ़ाड़ कर उसके एक हिस्सा को रस्सी बना कर थैले को बाँधा, तो उनका लक़ब ''ज़ातुन्नताक़ैन'' (दो कमरबंद वाली) पड़ गया, यह भी उनके लिए सआ़दत की बात थी। (अल-बिदाया वन्निहाया 2/190-192)

उधर पैग़म्बर अ़लैहिस्सलाम ने हज़रत अली रज़ि अल्लाहु अ़न्हु को वे अमानतें सुपुर्द फ़रमाई, जो आप के पास रखी हुई थीं कि सुबह को जिसकी जो अमानत है उसके पास पहुंचा देना, और अपने उस बिस्तर पर जहाँ आप आराम फ़रमाते थे, फ़रमाया कि यहाँ लेटे रहना, और अपनी ओढ़ने वाली चादर भी इनायत फ़रमा दी। आप दरे अक़्दस पर तशरीफ़ फ़रमा थे। आप के अंदर जाने के बाद दस बारा आदमी हथियार बंद होकर और चौकन्ना होकर दरे अक़्दस के चारों तरफ़ खड़े हो गए, और आपस में ख़ुशी के मारे चुपके चुपके गुफ़्तगू करने लगे कि ''यह मुहम्मद हमें डराते थे, देखो आज उनका क्या अंजाम होगा''? उस क़ाफ़िले में अबू जहल, उम"या और उ़क़बा भी है, गोया कि दुनिया के तमाम मलऊ़न, शक़ीयुल क़ल्ब और बद तरीन लोग वहाँ जमा थे, और उनका प्लान यह था कि जब आप आराम फ़रमा हों, तो रात के आख़िरी हिस्से में हमला किया जाए। नबी-ए-अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम अल्लाह के हुक्म से रात के किसी हिस्से में अपने दौलत कदा से बाहर तशरीफ़ लाए और क़ुरआन पाक की आयत:

(हम ने उनके आगे पीछे दीवार कर दी, और उन्हें ढांप दिया, उनको कुछ नज़र नहीं आ रहा था) तिलावत फ़रमा रहे थे। नबी-ए-अकरम अ़लैहिस्सलातु वस्सलाम उन्हीं लोगों के दरमियान से बहिफ़ाज़त बाहर तशरीफ़ लाए, और अपने हाथों में मिटी उठा कर हर एक के सर पर डाल दी, और हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ि अल्लाहु अ़न्हु के घर तशरीफ़ ले गए, और सुबह होने से पहले पहले उनके साथ निकल कर ''ग़ारे सौर'' तशरीफ़ ले गए। (अल बिदाया वन्निहाया, 2/190-191)

ग़ारे सौर बहुत ऊँचाई पर वाक़े है। आज भी आदमी अगर चढ़ना चाहे तो कई घंटे लगते हैं। जिस ग़ार में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने क़याम फ़रमाया वह बिल्कुल झाड़ झंकाड़ से भरा हुआ था, हज़रत अबू बक्र रज़ि अल्लाहु अ़न्हु ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को बिठा दिया, और कहा कि पहले मैं अंदर जाकर साफ़ करता हूँ जब बिल्कुल साफ़ हो जायेगा, तब आप को अंदर ले जाऊँगा, ऐसा न हो कि कोई कीड़ा काँटा हो और वह आप को तकलीफ़ पहुंचा दे, फिर पैग़म्बर अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फ़रमा हुए। (अल-बिदाया वन्निहाया 2/193)

उधर वे लोग हुज़ूर के निकलने के इन्तिज़ार में थे, तो शैतान एक आदमी की शकल में आया और कहा कि रात में यहाँ क्यों खड़े हो? उन्होंने कहा कि मुहम्मद के इन्तिज़ार में हैं, शैतान ने कहा कि वह तो चले भी गए, और अपने सर पर देखो मिटी पड़ी हुई है, यह तमाम लोग ज़च और ज़लील होकर रह गए, सारा प्लान ख़ाक में मिल कर रह गया, अंदर देखा तो हज़रत अली कर्मल्लाहु वजहहू हैं, उनको खींच कर मस्जिदे हराम तक लाये, और हुज़ूर के बारे में मालूम किया, हज़रत अली रज़ि अल्लाहु अ़न्हु ने फ़रमाया कि मुझे क्या मालूम हुज़ूर कहाँ गए? मैं तो यहाँ सो रहा हूँ, मजबूरन उनको छोड़ दिया, कभी इधर जायें और कभी उधर जायें, ताआँकि बिल्कुल ग़ारे सौर के दहाने पर पहुंच गए, अल्लाह तआ़ला की नुसरत और मदद कि अभी वह ग़ार जहाँ हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम और आप के रफ़ीक़े ग़ार हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ि अल्लाहु अ़न्हु चंद घंटे पहले तशरीफ़ ले गए थे, मकड़ी ने जाला तन दिया और कबूतर ने घोंसले बना लिए, ये लोग अंदर जाना चाहते थे, लेकिन यह सोच कर कि जिस जगह मकड़ी ने जाला तन रखा हो, उसका मतलब यह है कि काफ़ी दिनों से यहाँ कोई नहीं गया, और कबूतरी ने अंडे दे रखे हैं, यह जगह वीरान है, अल्लाह तआ़ला ने हिफ़ाज़त का इन्तिज़ाम फ़रमाया। (अल-बिदाया वन्निहाया, 2/195) (जारी)

# मोदी असर ग़ैर-बंगालियों में ही

## सौगात राय

**बंगाल चुनावों में इस बार भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी चुनौती बन कर ममता बनर्जी के सामने खड़ी हो गई है। तृणमूल कांग्रेस के कई नेता भाजपा का दामन थाम रहे हैं। ऐसे में, क्या ममता बनर्जी चुनावों की हैट्रिक लगा पाएंगी? तृणमूल किन मुद्दों के ज़रिए जनता का भरोसा फिर जीतने की कोशिश करेगी? इन सब पहलुओं पर पेश है तृणमूल कांग्रेस के सांसद सौगात राय से हुई बातचीत के प्रमुख अंशः-**

**प्रश्नः**- भाजपा इस बार पूरे जोर-शोर से चुनावों में उतर रही है। अमित शाह का दावा है कि 200 सीटें जीतेंगे। आपके लिए कितनी बड़ी चुनौती है?

**उत्तरः**- बहुत चुनौती नहीं है। टीएमसी को स्पष्ट बहुमत मिलेगा। जहां तक अमित शाह के दावे की बात है तो कोई कुछ भी कह सकता है। उनके लिए 100 सीटें भी जीतना मुश्किल होगा।

**प्रश्नः**- लेकिन लोकसभा चुनावों में भाजपा ने उम्मीद से कहीं अच्छा प्रदर्शन किया था?

**उत्तरः**- यह बात सही है कि भाजपा के लिए उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन था लेकिन अगर उन परिणामों के आधार पर विधानसभा सीटें देखे तो उस वक्त भी तृणमूल कांग्रेस को 150 से ज़्यादा और भाजपा को 100 के आस-पास सीटें मिलती। हमने बहुत काम किया है। पार्टी कार्यकर्ताओं में नया जोश भरा है। ग़रीब तबक़े तक जो हमारी योजनाएं चल रही हैं, उससे समर्थन बढ़ा है। हम 143 से ज़्यादा सीटें जीतेंगे।

**भाजपा तो लोगों को लड़ाने का ही काम करती है। ममता सरकार ने पिछले 10 वर्ष में लोगों को सांप्रदायिक हिंसा से दूर रखा है। क़ानून का राज है। लोगों को स्थिर सरकार दी है। हमारी योजनाएं हर तबक़े तक पहुंची हैं, जिसका लोगों को काफी लाभ मिल रहा है।**

**प्रश्नः**- माकपा और कांग्रेस एक बार फिर मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, यह कितनी बड़ी चुनौती है.?

**उत्तरः**- देखिए, हमारा स्पष्ट मानना है कि हमें भाजपा से टक्कर मिलने वाली है। माकपा-कांग्रेस तो टक्कर में ही नहीं हैं।

**प्रश्नः**- दस साल में कौन- कौन से काम किए हैं, जिससे आपको भरोसा है कि स्पष्ट बहुमत मिलेगा? भाजपा के ममता बनर्जी पर तुष्टिकरण और भ्रष्टाचार के आरोपों पर क्या कहना है?

**उत्तरः**- भाजपा तो लोगों को लड़ाने का ही काम करती है। ममता सरकार ने पिछले 10 वर्ष में लोगों को सांप्रदायिक हिंसा से दूर रखा है। क़ानून का राज है। लोगों को स्थिर सरकार दी है। हमारी योजनाएं हर तबक़े तक पहुंची हैं, जिसका लोगों को काफी लाभ मिल रहा है।

**प्रश्नः**- भाजपा के पास मज़बूत संगठन है, वह काफी आक्रामक और आधुनिक तरीक़े से चुनाव लड़ती है। ऐसे में आप उससे कैसे टक्कर लेंगे?

**उत्तरः**- हम यह सब अच्छी तरह से जानते हैं, इसके पीछे पैसा है। हमारे पास नहीं है लेकिन हम अपने संगठन के दम पर चुनाव लड़ेंगे। भाजपा मशीनरी का दुरुपयोग करती है। हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं यही भरोसा हमें जिताएगा।

**प्रश्नः**-भाजपा का आरोप है कि टीएमसी हिंसा का रास्ता अपना रही है, उसके कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है..?

**उत्तरः**- यह आरोप सही नहीं है। कुछ घटनाएं घटी हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि ममता बनर्जी हिंसा का रास्ता अपनाती हैं। भाजपा चीज़ों को बढ़ा-चढ़ा कर पेश करती है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा पर हुए हमले को ही देखिए, कैसे पेश किया गया। असल में वह तो बहुत स्थानीय स्तर की छोटी सी घटना थी। उसमें थोड़ी बहुत कुछ लोगों को चोट आई थी और गाड़ी का शीश टूटा था।

**प्रश्नः**- राज्यपाल के रवैये को कैसे देखते हैं? ऐसा लगता है कि चुनाव से पहले राष्ट्रपति शासन भी लग सकता है?

**उत्तरः**- उनका रवैया बहुत खराब है, वे भाजपा कार्यकर्ता जैसा व्यवहार करते हैं। जहां तक राष्ट्रपति शासन की बात है तो कानून के मुताबिक ऐसा करना मुश्किल है। सरकार बहुमत में है और पूरी मजबूती से काम कर रही है। फिर किस आधार पर ऐसा करेंगे। हम इस राज्यपाल के ख़िलाफ़ हैं और खुलकर उनका विरोध करते हैं।

**प्रश्नः**- तृणमूल कांग्रेस से शुभेन्द्र अधिकारी जैसे जनाधार वाले नेताओं ने भाजपा का दामन थामा है असंतोष से कैसे निपटेंगे?

**उत्तरः**- देखिए, थोड़ा बहुत असंतोष हो सकता है। वह भी स्थानीय स्तर पर लेकिन पार्टी में बड़े पैमाने पर कोई असंतोष नहीं हैं। शुभेन्द्र के साथ 6 लोग गए थे। 4-5 और भी जा सकते हैं। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होगा। चुनावों से पहले ऐसा होता आया है।

**प्रश्नः**- प्रशांत किशोर को लेकर भी पार्टी में असंतोष है, आपका क्या कहना है?

**उत्तरः**- प्रशांत किशोर अच्छा काम कर रहे हैं। वे पार्टी को अच्छी सलाह दे रहे हैं, चुनाव के लिए बेहतरी रणनीति भी बना रहे हैं। जहां तक उनके ख़िलाफ़ असंतोष की बात है तो वह केवल उसी को होगा, जिसको डर है कि उसकी रिपोर्ट अच्छी नहीं हैं ऐसे में उसका टिकट कट जाएगा।

प्रश्नः- ममता बनर्जी भाजपा पर आरोप लगाती रही हैं कि वह बाहरी लोगों के ज़रिए चुनाव लड़ रही है?

**भाजपा चीज़ों को बढ़ा-चढ़ा कर पेश करती है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा पर हुए हमले को ही देखिए, कैसे पेश किया गया। असल में वह तो बहुत स्थानीय स्तर की छोटी सी घटना थी। उसमें थोड़ी बहुत कुछ लोगों को चोट आई थी और गाड़ी का शीश टूटा था।**

**उत्तरः**- इसमें ग़लत क्या है। भाजपा का पूरा अभियान देखिए उसने बाहरी लोगों की फौज खड़ी कर दी है। रोज़ एक केंद्रीय मंत्री आकर यहां भाषण देते हैं। ये ऐसे लोग हैं, जिनका बंगाल से कोई संबंध नहीं है।

**प्रश्नः**- चर्चा है कि सौरभ गांगुली भाजपा का दामन थाम सकते हैं, इस पर आपका क्या कहना है..?

**उत्तरः**- हम नहीं चाहते हैं कि सौरभ राजनीति में आएं। अभी तक सौरभ ने ऐसी कोई इच्छा नहीं जताई। यह सब भाजपा की ओर से फैलाया जा रहा है। उनकी अपनी छवि है उन्हें राजनीति में नहीं आना चाहिए।

**प्रश्नः**- इन चुनावों में मोदी फैक्टर कितना असर डाल सकता है..?

**उत्तरः**- थोड़ा बहुत मोदी फैक्टर काम करेगा। वह भी ग़ैर बंगालियों में ही दिखेगा। जहां तक बंगालियों के ऊपर असर की बात है तो वहां कोई असर नहीं है। इसमें दोराय नहीं है कि हर जगह ममता भारी पड़ेंगी। ❑

# बना रहे हैं मज़बूत गठबंधन

## मोहम्मद सलीम

प्रश्नः- वामदल-कांग्रेस गठबंधन पिछली बार तो बहुत कारगर नहीं रहा था इस बार भाजपा और तृणमूल कांग्रेस को कितनी चुनौती दे पाएगा?

उत्तरः- हम लेफ्ट फ्रंट का विस्तार कर रहे हैं। इसके तहत हम सभी ग़ैर सांप्रदायिक दलों को एक साथ जोड़ रहे हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ कांग्रेस है। दलों के अलावा समूहों और व्यक्तिगत स्तर पर भी लोगों को अपने साथ जोड़ रहे हैं। ये वे लोग हैं, जो तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के विचारों से इत्तेफाक़ नहीं रखते हैं। यह एक मज़बूत विकल्प के रूप में खड़ा होगा। जहां तक 2016 की बात है, तो आज माहौल पूरी तरह बदला हुआ है।

प्रश्नः- तो क्या बिहार जैसा महागठबंधन होगा.?

उत्तरः- हम बिहार की नक़ल नहीं कर रहे हैं। महागठबंधन जैसा नाम नहीं देने वाले हैं। हम बंगाल की संस्कृति के आधार पर चल रहे हैं। हमारा लक्ष्य ममता को हटाता और भाजपा को रोकना है।

प्रश्नः- अगर आपका गठबंधन जीतता है तो क्या यह तय है कि माकपा का ही नेता मुख्यमंत्री बनेगा?

उत्तरः- देखिए अगर माकपा को अकेले भी बहुमत मिलता है तो भी हम गठबंधन की सरकार बनाएंगे। माकपा के पास वह अनुभव और प्रतिष्ठा है, जिससे वह गठबंधन की सरकार चला सके। ममता बनर्जी ने भी गठबंधन किया था, आज वे अकेले हैं। एनडीए के साथी भी उसे छोड़ रहे हैं, जबकि माकपा के साथ 17 दल हैं।

प्रश्नः- भाजपा और तृणमूल कांग्रेस में किसे नंबर वन विरोधी मानते हैं..?

उत्तरः- हर मीडिया यह सवाल पूछता है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। हम चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे हैं। हम केन्द्र की सत्ता में बैठी भाजपा और राज्य में बैठी तृणमूल कांग्रेस के ख़िलाफ़ हैं। हमारी लड़ाई दक्षिणपंथियों से है और आज उस ओर भाजपा और तृणमूल दोनों हैं।

प्रश्नः- चुनावों में हिंसा की बात भाजपा कर रही है.?

उत्तरः- जो लोग हिंसा करते हैं, वे इस समय तृणमूल और भाजपा दोनों में हैं। ये गुंडागर्दी, गोलाबाज़ी, कमीशन के लिए आपस में लड़ रहे हैं। ये चुनावी हिंसा नहीं है, यह सब लूट की लड़ाई है।

प्रश्नः- ठीक चुनाव से पहले भाजपा में तृणमूल और वामदलों के लोग शामिल हो रहे हैं.?

उत्तरः- यह भाजपा की कमज़ोर है। मीडिया भी उसके पक्ष में माहौल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ता हैं लेकिन ज़मीनी हक़ीक़त कुछ और होती है। अपना पलड़ा भारी करने के लिए भाजपा दूसरे दलों के लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए तोड़-फोड़ कर रही है।

प्रश्नः- ममता बाहरी बनाम स्थानीय मुद्दा उठा रही है..?

उत्तरः- यह गलत राजनीति है। संविधान के अनुसार इस देश का कोई भी व्यक्ति कहीं से भी आकर चुनाव लड़ सकता है। मोदी भी तो गुजरात से आकर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ते हैं। बंगाल में उत्तर प्रदेश, बिहार और दूसरे राज्यों से आकर लोग बसे हैं। इसमें हर्ज क्या हैं तृणमूल, भाजपा इस तरह की राजनीति कर लोगों में उन्माद पैदा करते हैं। यह लोग धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र के नाम पर लोगों को बांटना चाहते हैं।

प्रश्नः- गृहमंत्री अमित शाह ने एक बार फिर सीएए, एनआरसी का मुद्दा उठाया है..?

उत्तरः- अमित शाह जो भूत दिखा रहे थे। अब उसको सामने लाने का समय आ गया है। चुनाव के समय यह निकलता है यह केवल विभाजन की राजनीति करने के लिए है। इसके तहत बंगाल और ग़ैर-बंगाली और हिन्दू मुस्लिम को बांटना है। ❑❑

# आम भारतीय की ज़रूरतों की उपज है कांग्रेस

कांग्रेस ने अपनी स्थापना के 136 वर्ष पूरे कर लिए हैं। भारत की आज़ादी की लड़ाई से लेकर आधुनिक भारत के निर्माण में कांग्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका रही हैं आज़ादी के बाद से 2019 तक भारत के 17 आम चुनाव में से कांग्रेस ने 7 में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया और 4 में सत्तारूढ़ गठबंधन का नेतृत्व किया। लगभग आधी सदी तक कांग्रेस केन्द्र सरकार का हिस्सा रही। आज भले ही अधिकांश राज्यों में कांग्रेस की सरकार नहीं है, लेकिन कांग्रेस ही देश का एक मात्र राजनैतिक दल है, जिसका कार्यकर्ता भारत के उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम के हर गांव में मिल जाएगा।

28 दिसंबर 1885 को कुछ बुद्धिजीवियों ने भारत के लोगों की ज़रूरतों उनकी समस्याओं के विमर्श के लिए एक मंत्र की ज़रूरत महसूस की जो तत्कालीन हुक्मरानों के समक्ष भारत की जनता की आवाज़ बन सके सरकार के द्वारा बनाई जा रही नीतियों में भारत की ज़रूरतों को स्थान दिलवाया जा सके। इन्हीं उद्देश्यों को लेकर 17 सदस्यों ने कांग्रेस की स्थापना की, जिसमें एओ हयूम, दादा भाई नौरोजी, व्योमेश चन्द्र बैनर्जी, दिनशा वाचा प्रमुख थे। कांग्रेस का पहला अधिवेशन व्योमेश चन्द्र बैनर्जी की अध्यक्षता में मुम्बई में हुआ। भारतीयों की समस्याओं को उठाने के उद्देश्य के लिए गठित की गई कांग्रेस पार्टी बहुत जल्दी ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की मुखर विरोधी बन गयी।

गठन से लेकर भारत की आज़ादी तक कांग्रेस के लगभग 15 मिलियन सदस्य बन गए थे। गुलाम भारत के लोगों में राजनैतिक चेतना जागृत कर उनके आज़ाद देश की ललक पैदा करना एक कठिन बड़ा काम था, जब तक लोगों में आज़ादी और स्वराज की ज़रूरत की चेतना जागृत नहीं होगी, अंग्रेजी शासन के ख़िलाफ़ कोई भी आंदोलन खड़ा नही हो सकता, इस बात को कांग्रेस ने भली-भांति समझ लिया था, इसीलिए कांग्रेस ने शुरू से ही अपने विरोध के कार्यक्रमों में आम आदमी को जोड़ा और सामूहिक नेतृत्व पर ज़ोर दिया। 1915 में महात्मा गांधी के भारत आगमन के बाद उन्हें कांग्रेस की अध्यक्षता सौंपी गई। 1919 तक में गांधी कांग्रेस के प्रतीक पुरुष बन गए ओर इसके बाद कांग्रेस ने देशभर में अंग्रेजी हुकूमत के अत्याचारों के ख़िलाफ़ जनांदोलनों को खड़ा करना शुरू किया। छोटे-छोटे विरोध आंदोलनों की श्रृंखला धीरे-धीरे राष्ट्रीय आंदोलन में परिवर्तित हो गई। सविनय अवज्ञा, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, पूर्ण स्वराज आंदोलन में परिवर्तित होकर पन्द्रह अगस्त 1947 को आजाद भारत के पूर्ण लक्ष्य को अंततः प्राप्त कर ही लिया गया।

कांग्रेस आज़ादी का लक्ष्य प्राप्त करने में इसलिए सफल हुई, क्योंकि वह लोकतांत्रिक मूल्यों को लेकर आगे बढ़ रही थी। आज़ादी की लड़ाई में कांग्रेस किसी एक वर्ग का नहीं, बल्कि सम्पूर्ण भारत की अगुआई कर रही थी। कांग्रेस में कई विचारधाराएं थीं गांधी जी सहित कांग्रेस के नेतृत्वकर्ताओं ने वैचारिक मतभिन्नता का पूरा सम्मान किया तथा विभिन्न विचारों को लेकर स्वतंत्र भारत के एक लक्ष्य के साथ कांग्रेस दुनिया के सबसे बड़े सफल अहिंसक आंदोलन को चलाने में कामयाब हुई। यह कहना अतिश्योक्ति नहीं होगी कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कांग्रेस भारत के जनमानस की आईना थी। सारा भारत कांग्रेस के साथ था, सिर्फ साम्प्रदायिक जातिवादी और अंग्रेजों के प्रति श्रद्धा रखने वाले दल ज़रूर कांग्रेस के ख़िलाफ़ थे। कांग्रेस के बड़े नेता दादा भाई नोरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, लोकमान्य तिलक, गांधी जी, भगत सिंह, पंडित जवाहर लाल नेहरू, सुभाष चन्द्र बोस, सरदार पटेल, राजेन्द्र प्रसाद, भीम राव अंबेडकर, सी. राजगोपालाचारी, आचार्य नरेन्द्र देव, मौलाना आज़ाद, मदन मोहन मालवीय आदि अनेकों नेताओं ने नेतृत्व और त्याग नैतिकता के ऊंचे मानदंडों को स्थापित किया था। आज़ादी के बाद छोटे-छोटे रजवाड़ो-रियासतों को समाहित कर लोकतांत्रिक भारत के निर्माण के साथ समानता वाले भारत का निर्माण, सबको समान अवसर के साथ सामाजिक और लैंगिक समानता का सुनिश्चित करना बहुत बड़ी चुनौती थी। आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू जानते थे कि वह सारे लक्ष्य तभी फलीभूत हो सकते हैं, जब भारत आर्थिक रूप से सुदृढ़ और सुशिक्षित और स्वस्थ हो। इसीलिए नेहरूजी ने सिंचाई परियोजनाओं के साथ बड़े कल-कारखानों की नींव साथ में रखी। नेहरूजी विज्ञान और संस्कृति के सामंजस्य वाले भारत की कल्पना की थी। यही कारण था कि उन्होंने देश में आईआईएम, आईआईटी जैसे अभियांत्रिकी प्रबंध संस्थानों से लेकर बेहतरीन चिकित्सा संस्थान अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना की।

पंडित नेहरू के बाद की कांग्रेस सरकारों ने उनके द्वारा स्थापित इस मज़बूत नींव पर आधुनिक भारत की शानदार इमारत की स्थापना पर कोई असर नहीं छोड़ी। देश की सामयिक ज़रूरत के अनुसार कांग्रेस ने समय-समय पर प्राथमिकता को बदल कर योजनाओं को बनाया। आज़ादी के पहले स्वतंत्रता आंदोलन, आज़ादी के बाद गणतंत्र का निर्माण, संविधान आंदोलन, आजादी के बाद गणतंत्र का निर्माण...संविधान निर्माण प्राथमिकता में थे। नेहरूजी के बाद शास्त्री जी के समय अनाज देश की सुरक्षा को लक्ष्य रख कर, 'जय जवान जय किसान' का नारा किया गया। इंदिराजी ने हरित क्रांति, बीस सूत्री कार्यक्रम, अंतरिक्ष कार्यक्रम, परमाणु कार्यक्रम के ज़रिए सुदृढ़ भारत के लक्ष्य को प्राथमिकता में रखा। राजीव गांधी जब भारत के प्रधानमंत्री बने तब देश को 21वीं सदी की ओर ले जाने के लिए कांग्रेस की प्राथमिकता में सूचना प्रौद्योगिकी और कम्प्यूटर क्रांति थी। पंचायतों का सशक्तीकरण कर सत्ता के विकेन्द्रीकरण का मार्ग भी खोला गया। पीवी नरसिंहाराव जी के समय आर्थिक उदारीकरण को अपना कर वैश्विक व्यापारिक जगत में भारत को मज़बूती से खड़ा करने का प्रयास किया गया। यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी के मार्ग दर्शन तथा मनमोहन सिंह के नेतृत्व में आर्थिक सुधारों के साथ खाद्य सुरक्षा क़ानून, सूचना के अधिकार, महात्मा गांधी रोज़गार गारंटी, शिक्षा का अधिकार, भू-अधिग्रहण जैसे कानूनों को लाकर कांग्रेस ने आम आदमी के जीवन स्तर को सुधारने का प्रयास किया। 2014 में केन्द्र की सत्ता से जाने के बाद राहुल गांधी के नेतृत्व में एक सजग विपक्ष की भूमिका निभा रही है। बहुमत के अतिवादी चरित्र का विरोध जिस बेबाकी और निडरता से राहुल गांधी कर रहे हैं, वह कांग्रेस के उन्हीं मूल्यों की उपज है, जिन मूल्यों को लेकर कांग्रेस ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक आंदोलन और भारत के सबसे बड़े राष्ट्रवादी आंदोलन 'भारत की आज़ादी की लड़ाई' को लड़ा था। ❑❑



# डिज़ाइनर प्रिंट के क्षेत्र में संवारिए कैरियर

भारत में विशेषकर उत्तरी भारत में शहरी संस्कृति में यह बात तेज़ी आ रही है कि शादियों का आयोजन आमतौर पर हल्की सर्दियों में रखने को वरीयता दी जाती है। आजकल सदी का सर्द मौसम है इस मौसम में शदियों की बहार आई हुई हैं सर्दी का मौसम शादियों के लिए अनुकूल इसलिए माना जा रहा है इन दिनों में फंक्शन में कपड़े को बेहतरीन तरह से पहना जा सकता है, न गर्मी वाला पसीना, न चीप-चीप, न ऐसी की टेंशन गुडलुक बना रहता है। फैशन हर पल बदलता है, मगर शादियों के इस सीजन में प्रिंट का जलवा बरक़रार है। बड़े बड़े डिजाइनर प्रिंट को न सिर्फ रोज़मर्रा के कपड़ों में बल्कि पारंपरिक और ब्राइडल परिधान में भी इस्तेमाल कर रहे हैं। कैजुअल विअर में जहां प्रिंट को स्पोर्टी लुक के लिहाज़ से पहना जा सकता है वहीं इसमें देसी लुक भी दिया गया है। चिकनकारी मेटाफिक, पैचवर्क, एम्ब्रायडरी हर चीज़ का इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रिंट न सिर्फ कैजुअल बल्कि पारंपरिक परिधानों की भी शोभा बढ़ा रहा है। डिजाइनर प्रिंट को न सिर्फ युवाओं के कुर्ते और जैकेट में इस्तेमाल कर रहे हैं बल्कि मुगल काल के जैसे लहंगे में भी नए फैशन की तरह इस्तेमाल हो रहे हैं। चाहे वह फलर्टी ट्रेल गाउन हो या ग्लैमरस गाउन, हर जगह प्रिंट का बोलबाला है। इस सीजन में ब्राइडल कपड़ों में भी प्रिंट का इस्तेमाल किया जा रहा है। फैब्रिक चाहे हल्के जार्जेज हो या भारी वेलवेट। इसमें की गई हेवी गोल्डन एम्ब्रायडरी खूब फबती है। डिजाइनर ब्राइडल कलर में मरून, वाइन कलर, गोल्डन कलर का खूब इस्तेमाल करते हैं। इन पर ऐसी कारीगरी की जाती है कि यह दुल्हन को एक नया सौंदर्य देते हैं। भारत गोल्ड जरदोजी एम्ब्रायडरी लहंगों और ब्राइडल कपड़ों पर ऐसे किया जाता है कि मानो प्रिंट किया गया है। ऐसे में अगर आप एक नए लुक में लिखना चाहते हैं तो फ्लोरल प्रिंट बेहतर हैं। पेस्टल शेड पर फ्लोरल प्रिंट के क्या कहनें!

इसे पहनकर आप भीड़ से अलग दिखेंगी। शादी की भागदौड़ में अक्सर हम भारी भरकम कपड़े पहन कर परेशान हो जाते हैं। ऐसे में हल्के प्रिंट के कपड़े साथ में गोल्डन एम्ब्रायडरी की साड़ी इस मौक़े के लिए बेहतरीन हैं। रोज़मर्रा की बात करें तो इसमें तो प्रिंटेड कपड़ों का बोलबाला है। ब्लैक रेड, मरून, पीला हर कपड़ों पर प्रिंट फबता है। अगर आप जींस या टॉप पहनती हैं तो इसमें भी अब प्रिंट मिल जाते हैं। जींस की जगह अब प्रिंटेड जेग्गिंस ने ले ली है। ये देखने में जितने आकर्षक लगते हैं उतना ही पहनने में आरामदायक। प्रिंटेड टी-शर्ट न सिर्फ युवतियों बल्कि युवाओं के लिए भी पसंद किया जा रहा है। शादी के सीजन में युवाओं के लिए भी प्रिंटेड में बहुत कुछ हैं पिंटेड ब्लेजर को अगर पेंसिल ट्राउजर के साथ पहना जाए, तो यह क्लासी लुक देता है। अगर आप शेरवानी के शौक़ीन हैं, तो प्रिंट शेरवानी पर सुनहरा एम्ब्रायडरी कर पहनें। आप भीड़ से बिल्कुल अलग दिखेंगी। शादी में अगर थोड़ा शाही अंदाज़ चाहते हैं तो मरून, ब्लू और पिस्ता रंग की शेरवानी और ब्लेजर पहनें। यह आपको बेहद ही फैशनेबल दिखाएगा। सर्दियों में वेलवेट बेहद पसंद किया जाता है तो कटेम्परी लुक के लिए प्रिंटेड वेलवेट कोट पहन सकते हैं। इसके साथ चाहें, तो स्कार्फ कैरी कर सकते हैं। बनारसी कपड़ों में भी बेहतरीन प्रिंट मिल जाते हैं और ये फैशन का हिस्सा बन चुके हैं। इस तरह फार्मल, पाम्परिक या ब्राइडल कुछ भी आप प्रिंट में चुन फैशन में शामिल हो सकते हैं। आजकल इतनी सारी वैरायटी आ गई है कि आपके लिए विशेषकर मैट्रोपोलिटन शहरों में सर्दियों में शादी ब्याह और फंक्शन में आपके पास अनेक ऑपशन्स होते हैं। इसलिए तो कहते हैं कि सर्द मौसम में फंक्शन को सही इंजाय किया जा सकता है, बमुकाबले गर्म मौसम के। ❑❑

## इस्लामी दुनिया

### पाक में सीनेट चुनाव के लिए संविधान संशोधन करेगी सरकार

इस्लामाबाद : पाकिस्तान के मंत्रिमंडल ने सीनेट का चुनाव ओपन मतपत्र से कराने के लिए संविधान में संशोधन के लिए संसद में एक विधेयक प्रस्तुत करने का निर्णय किया हैं पीएम इमरान ख़ान की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया।

### राजकपूर की हवेली बेचने से मकान मालिक का इंकार

पेशावर : राज कपूर का पेशावर स्थित पैतृक मकान उसके मालिक ने खैबर पख्तूनख्वा सरकार की ओर से निर्धारित कीमत पर बेचने से इंकार कर दिया है। पाक की ख़ैबर पख्तूनख्वा सरकार ने राज कपूर के 151.75 वर्ग मीटर मकान की कीमत 1.5 करोड़ तय की थी। सरकार ने दिलीप कुमार व राजकपूर के पैतृक घरों की खरीद के लिए 2.35 करोड़ रुपए जारी करने को मंज़ूरी दी थी। हवेली के मालिक हाजी साबिर ने कहा कि मकान की कीमत बहुत ही कम लगाई गई है।

### पाकिस्तान की जेल में 18 वर्ष रहने के बाद महाराष्ट्र लौटीं हसीना बेगम

औरंगाबाद : 18 वर्ष तक पाकिस्तान की जेल में रहने के बाद महाराष्ट्र के औरंगाबाद की रहने वाली 65 वर्षीय हसीना बेगम आख़िरकार अपने घर लौट आई। वे 2002 में पति के रिश्तेदारों से मिलने पाकिस्तान गई थीं। लाहौर में पासपोर्ट खो जाने के बाद उन्हें पाकिस्तानी अधिकारियों ने जेल में डाल दियाथा। हसीना औरंगाबाद के सिटी चौक इलाके के राशिदपुरा की रहने वाली है। उनकी शादी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के रहने वाले दिलशाद अहमद से हुई थी, जिनके रिश्तेदार पाकिस्तान में रहते हैं।

### एमएयू : टाइम कैप्सूल में 100 साल का इतिहास 100 साल के लिए सहेजा गया

अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में गणतंत्र दिवस खास ढंग से मनाया गया। विक्टोरिया गेट पर स्टील के 1.5 टन वजनी कैप्सूल में 100 सालों का इतिहास अगले 100 सालों के लिए सहेजा गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा जारी किया गया डाक टिकट और उनके भाषण को भी टाइम कैप्सूल में सुरक्षित रखा गया है ताकि आने वाले पीढ़ी भी इससे संबंधित इतिहास की जानकारी ले पाए।

# उपभोक्ता संरक्षण की चुनौती

**जयंतीलाल भंडारी**

आज के बाज़ारवादी युग में उपभोक्ता संरक्षण बड़ी ज़रूरत के रूप में सामने आ चुका है। जिस तेज़ी से आर्थिक गतिविधियां बढ़ रही हैं और अर्थव्यवस्थाएं बाजारोन्मुख हो चुकी हैं, उसमें उपभोक्ता ही सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण घटक है। बिना उपभोक्ता के बाजार की कल्पना संभव ही नहीं है। ऐसे में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा भी सरकारों की बड़ी ज़िम्मेदारी हैं, ख़ासतौर पर वैश्विक बाज़ार जब डीजिटल रूप में तब्दील हो चुका हो। पिछले एक वर्ष में कोरोना महामारी के बीच ई-कॉमर्स का चलन तेजी से बढ़ा है। भारत में भी ऑनलाइन बाज़ारों और कंपनियों की भरमार देखने को मिल रही हैं और कई बड़ी कंपनियों इनमें स्थापित भी हो चुकी हैं। भारत ही नहीं दुनिया के सभी देशों में जैसे-जैसे ई-कॉमर्स और डिजिटल लेन-देन बढ़े हैं, वैसे-वैसे उपभोक्ताओं को बढ़ती हुई डिजिटल धोखाधड़ी और बढ़ते हुए साइबर अपराधों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी ओर परंपरागत बाज़ारों में भी उपभोक्ताओं के साथ तरह-तरह की धोखाधड़ी के मामलों में कमी देखने को नहीं मिल रही है। यह चुनौती ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में कहीं ज़्यादा है।

जिस उपभोक्ता को बाज़ार की आत्मा कहा जाता है, उसे अभी भी बाज़ार में तरह-तरह की धोखाधड़ी का सामना करना पड़ता हैं आम उपभोक्ता खाद्य सामग्री में मिलावट, बिना मानक की वस्तुओं की बिक्री, अधिक दाम, कम नाप-तौल जैसी समस्याओं से आए दिन रूबरू होते हैं। इतना ही नहीं, बड़ी मात्रा में हरी सब्जियां बाजारों में रंगी जाती हैं, दूध और तेल में मिलावट का धंधा किसी से छिपा नहीं है। मिठाइयों और मावे में भी मिलावट की घटनाएं देखने को मिलती रहती है। ज़ाहिर है, उपभोक्ताओं की जेब ही नहीं कट रही, बल्कि उनके स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है, ऐसे में देश के कोने-कोने में उपभोक्ता संरक्षण संबंधी विभिन्न चुनौतियां बढ़ गई हैं।

हालांकि हर वर्ष चौबीस दिसंबर को देश में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। इस दिन 1986 में राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण कानून लागू किया गया था। इसमें कोई संदेह नहीं कि उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986 को उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करने वाले और उपभोक्ताओं को न्यायिक अधिकारों के माध्यम से मुआवज़ा सुनिश्चित करने वाले सशक्त कानून के रूप में रेखांकित किया गया हैं इस क़ानून ने भारत में उपभोक्ता आंदोलन को एक आंदोलन का रूप दे दिया है। इस क़ानून के तहत उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा के मद्देनज़र निर्माताओं, सेवा प्रदाताओं और सरकार द्वारा किए जाने वाले सभी कार्य कलापों को सम्मिलित किया गया। साथ ही उपभाक्ता संरक्षण में व्यापारियों और उत्पादकों द्वारा उपभोक्ता विरोधी व्यवहारों के ख़िलाफ़ आश्वासन भी शामिल किए गए हें, जिनसे उपभोक्ताओं को ठगी से बचाया जा सके और उनकी शिकायतों का त्वरित निपटान किया जा सके। लेकिन उपभोक्ता संरक्षण क़ानून 1986 लागू होने के बाद भी स्थिति यह है कि देश के उपभोक्ताओं के साथ धोखाधड़ी की घटनाओं में कोई कमी नहीं आई हैं पिछले एक डेढ़ दशक में लगातार यह महसूस किया गया कि वैश्वीकरण और ई-कॉमर्स के दौर में भारत में उपभोक्ता अधिकारों के संरक्षण के लिए एक नए और व्यापक कानून होने चाहिए। इसी परिप्रेक्ष्य में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को निरस्त करके 6 अगस्त, 2019 प्रतिस्थापित किया गया और इसे पिछले साल 20 जुलाई को लागू किया गया था।

इस समय कोविड-19 क बीच देश में उपभोक्ता बाजार के बदलते स्वरूप, ई-कॉमर्स और डिजिटलीकरण के नए दौर में नए उपभोक्ता कानून का कारगर साबित हो सकता है। यदि हम नए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की तस्वीर देखें तो पाते हैं कि इसके तहत उपभोक्ताओं के हितों से जुड़े विभिन्न प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए कई नियमों को प्रभावी किया गया हैं इनमें उपभोक्ता संरक्षण (सामान्य) नियम 2020, उपभोक्ता संरक्षण (उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग) नियम 2020, उपभोकता संरक्षण (मध्स्थता) नियम 2020, उपभोक्ता संरक्षण (केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद) नियम 2020 और उपभोक्ता संरक्षणा (ई कॉमर्स) नियम 2020 आदि शामिल हैं ज़ाहिर है, नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम न केवल पिछले 1986 के अधिनियम की तुलना में अधिक व्यापक हैं, बल्कि इसमें उपभोक्ता अधिकारों का बेहतर संरक्षण भी किया गया है। नए उपभोक्ता अधिनियम के तहत केन्द्रीय स्तर पर एक केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) का गठन भी 24 जुलाई, 2020 को किया गया। इसके तहत उपभोक्ता के अधिकारों की रक्षा के लिए सीसीपीए को शिकायतों की जांच करने, असुरक्षित वस्तुओं व सेवाओं को वापस लेने के आदेश देने, अनुचित व्यापार व्यवस्थाओं और भ्रामक विज्ञापनों को रोकने के आदेश देने और भ्रामक विज्ञापनों के प्रकाशकों पर जुर्माना लगाने के अधिकार प्रदान किए गए हैं। पहली बार उपभोक्ता संरक्षण क़ानून के दायरे में ई-कॉमर्स, ऑनलाइन, प्रत्यक्ष बिक्री और टेलीशापिंग कंपनियों को भी इसके दायरे में लाया गया है।

महत्वपूर्ण ख़ास बात यह है कि नए उपभोक्ता क़ानून से जहां अब एक करोड़ रुपए तक के मामले ज़िला विवाद निवारण आयोग में दर्ज कराए जा सकेंगे, वहीं एक करोड़ रुपए से अधिक लेकिन दस करोड़ रुपए तक राशि के उपभोक्ता विवाद राज्यस्तरीय आयोग में दर्ज कराए जा सकेंगे। राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में दस करोड़ रुपए से अधिक मूल्य वाले उपभोक्ता विवादों की सुनवाई होगी। यह बात भी महत्वपूर्ण है कि नए अधिनियम में ज़िला आयोग के निर्णय की अपील राज्य आयोग में करने की समयावधि को तीस दिन से बढ़ाकर पैंतालीस दिन किया गया है। इसी तरह किसी उत्पादक और विक्रेता के विरुद्ध शिकायत अभी तक उसके क्षेत्र में ही दर्ज कराई जा सकती थी। लेकिन अब नए अधिनियम के तहत उपभोक्ता के आवास एवं कार्य क्षेत्र से भी शिकायत दर्ज कराई जा सकेगी। नए उपभोक्ता क़ानून के तहत दावा अब उपभोक्ता अदालत में ही किया जा सकेगा। मध्यस्थता के ज़रिए मामलों के निपटान का प्रावधान भी इस क़ानून में किया गया है। भ्रामक विज्ञापनों के मामलों में सज़ा के कड़े प्रावधान नए क़ानून में है। ऐसे विज्ञापनों के मामले में विज्ञापन करने वाली हस्तियों को भी जवाबदेह माना गया है और उन पर भी जुर्माना लगाया जा सकेगा। ज़ाहिर है, नया उपभोक्ता संरक्षण अधि नियम भारत के बढ़ते हुए विविध तापूर्ण उपभोक्ता बाज़ार के लिए कारगर साबित होगा।

देश के करोड़ों उपभोक्ता रिश्वतखोरी के चिंताजनक परिदृश्य के बीच उपभोक्ता संतुष्टि से बहुत दूर दिखाई देते हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने भ्रष्टाचार पर अपनी रिपोर्ट एशिया सर्वे में बताया है कि एशिया में सर्वाधिक रिश्वतखोरी भारत में है। यह सर्वे पिछले साल जुलाई से सितंबर के बीच छह सरकारी सेवाओं-पुलिस, अदालत, सरकारी अस्पताल, पहचान पत्र लेने की प्रक्रिया और बिजली, पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए रिश्वत दिए जाने संबंधी प्रश्नों के जवाब पर आधारित है। भारत में उन्तालीस प्रतिशत लोगों ने कहा कि उन्हें सरकारी सुविधाओं की इस्तेमाल करने के लिए रिश्वत देनी पड़ी। देश में व्याप्त रिश्वतखोरी को लेकर सैंतालीस प्रतिशत भारतीयों की आम राय यह है कि बीते एक वर्ष में देश में रिश्वतखोरी बढ़ी है। इससे स्पष्ट होता है कि रिश्वतखोरी उपभोक्ताओं की संतुष्टि के मामले में बड़ी बाधा बनी हुई हैं निश्चित रूप से रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार केवल कुछ रुपयों की बात नहीं होती है, बल्कि इसका सबसे ज़्यादा नुकसान देश का ग़रीब और ईमानदार उपभोक्ता उठाता है। देश की व्यवस्था पर उपभोक्ताओं का जो भरोसा होता है, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार उस भरोसे पर हमला करते हैं। इसमें कोई दो मत नहीं है कि सरकार ने भ्रष्टाचार को कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं, लेकिन उस अनुपात में सफलता कम मिल पाई है उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा तभी संभव है जब घूसखोरी और भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए और सख़्त क़ानून बनें और उन पर अमल में सख़्ती हो। ❑❑

## किस्मत के मारे, शाहनवाज़ बेचारे

अटल सरकार में जब उन्होंने 1999 में शपथ ली थी तो वे महज़ 31 वर्ष के थे। यह अटल-आडवाणी का दौर था और संयोग यह कि वे दोनों के चहेते थे। सब कुछ उनके अनुकूल था, लिहाज़ा तरक्क़ी की सीढ़ियां भी तेजी से चढ़ते गए। पहले उन्हें राज्यमंत्री बनाया गया, बाद में उसी सरकार ने उन्हें स्वंत्र प्रभार का राज्यमंत्री बना दिया गया और कैबिनेट मंत्री का प्रमोशन भी अटल जी ने उन्हें अपनी उसी सरकार में दे डाला था। 2004 का लोकसभा चुनाव जब वे हार गए तो 2006 में उन्हें उपचुनाव के ज़रिए लोकसभा पहुंचाया गया। तब पार्टी के ही तमाम लोग शाहनवाज़ हुसैन की किस्मत पर रश्क़ करने लगे थे। भाजपा दफ्तर में हंसी मज़ाक में ही सही, लेकिन तमाम लोग उनसे यह पूछ लेते थे कि अटलजी-आडवाणी जी को मोहने की तरकीब उन्हें भी बता दें। एक सच यह भी कि वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता है। 2014 आते-आते भाजपा अटल आडवाणी की नही रह गई थी और बदकिस्मती यह भी कि मोदी लहर में भी शाहनवाज़ हुसैन लोकसभा चुनाव हार गए। यह हार ही उन्हें हाशिए पर लेकर चली गई। अगर वे जीत जाते तो पार्टी पर ज़रूर अपने एक पूर्व केन्द्रीय मंत्री को कैबिनेट में लेने का दबाव होता। ऐसा कोई दबाव था नहीं, सो इन पांच सालों में ख़ुद को समायोजित करवाने की शाहनवाज़ की कोशिशों का कोई फल नहीं निकला। 2019 के चुनाव में तो स्थिति यह बनी कि उन्हें टिकट ही नहीं मिला। वे जिस सीट से लड़ते थे वह सीट पार्टी ने जेडीयू के लिए छोड़ दी। राजनीतिक गलियारों में यह खुलकर माना गया कि मौजूदा लीडरशिप के साथ उनके समीकरण का न बैठ पाना ही उनके लिए परेशानी का सबब बना। इस बीच 2015 और 2020 के विधानसभा में पार्टी ने टिकट ऑफर किया, लेकिन उन्होंने कर दिया क्योंकि वे खुद को राष्ट्रीय राजनीति में देखना चाहते थे। अब जब कोई और विकल्प नहीं रहा तो उन्होंने विध ान परिषद की सदस्यता स्वीकार कर ली। शाहनवाज़ हुसैन बिहार के रहने वाले हैं। उनके पिता प्राईमरी स्कूल में टीचर थे। शाहनवाज़ का सपना बचपन से ही राजनीति में आने का था, हालांकि उनके परिवार से कभी कोई राजनीति में नहीं रहा। शाहनवाज़ ने अपना लोकसभा चुनाव 1996 में लड़ा, लेकिन हार गए थे।

# मिलावट का घातक रोग

**अखिलेश आर्येंदु**

हाल ही में शहद के तेरह नमूनों की जांच हुई, जिसमें महज़ तीन नमूने ही शुद्धता के मानक पर खरे उतरे। सीएसई यानि विज्ञान एवं पर्यावरण केन्द्र की रिपोर्ट के मुताबिक ठंडे पेयों में 2003-06 के बीच जांच के दौरान जो मिलावट पाई गई थी, उससे भी खतरनाक मिलावट शहद में पाई गई। शहद के जिन ब्रांडों में मिलावट पाई गई, वे देश के नामी गिरामी ब्रांड हैं। आयुर्वेदिक उत्पाद बनाने वाली ये कंपनियां करोड़ों लोगों के विश्वास पर खरी मानी जाती रही हैं। शहद में मिलावट करने वाले इन ब्रांडों में फ्रक्टोज और चीनी मिलाई जाती है। सीएसई द्वारा की गई ताज़ा जांच में शहद में सतहत्तर प्रतिशत तक मिलावट पाई गई हैं ग़ौरतलब है कि शहद में चीनी मिलावट पाई गई हैं। गौरतलब है कि शहद में चीनी मिलाए जाने की बात गांव-देहात में कही जाती है। एक जर्मन प्रयोगशाला में शहद के नमूनों की जांच में कई मशहूर कंपनियों के इस उत्पाद को शामिल किया गया था। जिन बाईस नमूनों की जांच की गई उनमें पांच ही शुद्धता के मानक पर खरे उतरे। जांच में यह बात भी सामने आई है कि ई-कॉमर्स वेबसाइट पर ऐसे सिरप की बिक्री हो रही है जो जांच को भी भ्रम में डाल सकते हैं

नई जांच से आम जनता का नामी गिरामी ब्रांडों के ऊपर से विश्वास खत्म होना तय है। आयुर्वेद की दुनिया के जिन बड़े नामों पर लोग सालों से यकीन करते आ रहे थे, वहीं नई जांच में खरे नहीं उतरे। इससे आयुर्वेद जगत के प्रति भी बढ़ते लोगों के रुझान में कमी आ सकती है। अब मामला महज़ शहद का नहीं रह गया है, बल्कि बड़े ब्रांडों के सभी उत्पाद का है बाकी आयुर्वेदिक उत्पादों में उक्त कंपनियां मिलावट कर रही हैं या नही! गौरतलब है कि जब ठंडे पेयों की जांच 2003 और 2006 के बीच हुई थी और उनमें ज़हरीले रसायनों की मिलावट की बात सामने आई थी, तब ठंडे पेय बनाने वाली कंपनियों के लाइसेंस रद्द करने की माग उठी थी। अब जब आयुर्वेदिक दवाओं और अन्य उत्पादों को बनाने वाली मशहूर भारतीय कंपनियों द्वारा मिलावट करने की बात सामने आई है, तो क्या सरकार इन कंपनियों के ख़िलाफ़ कोई सख़्त क़दम उठाएगी?

यों 2006 से ही मिलावट करने वाली कंपनियों और लोगों के ख़िलाफ़ सख़्त सज़ा का प्रावधान है, जिसमें उम्र क़ैद तक की व्यवस्था है। लेकिन कानून के हाथ की अपेक्षा कानून तोड़ने वालों के हाथ शायद ज़्यादा बड़े और माहिर हैं। यही वजह है कि मिलावट करने वाले ऊंची पहुंच और पैसे के बल पर साफ बच निकलते हैं। केन्द्र की राजग सरकार जो भ्रष्टाचार, मिलावटखोरी, कालाबाज़ारी, आतंकवाद और कर्मचारी के ख़िलाफ़ सख़्त कदम उठाने और पारदर्शी शासन देने की बात करती रहती है, क्या मिलावट के ख़िलाफ़ देशव्यापी अभियान चलाएगी? दूसरा प्रश्न यह है कि जो कंपनियां कहीं न कहीं स्वदेशी का झंडा उठा कर लोगों को स्वदेशी के नाम पर अपनी तरफ आकर्षित करती रही है, उन कंपनियों या उसी तरह की कार्रवाई करेगी, जैसी अन्य कंपनियों के ख़िलाफ़? मिलावट की समस्या कोई नई नहीं है। इतने सख़्त क़ानून के बावजूद सारे देश में मिलावट की धूम मची हुई है कि किसी भी उत्पाद पर यकीन करना मुश्किल हो गया है। शुद्धता के नाम पर जब आज जैविक उत्पादों की बात दुनियाभर में आगे बढ़ रही है, तो ऐसे में रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाले उत्पादों में हो रही मिलावट कई तरह के सवाल खड़े करती है।

ग़ौरतलब है कि मिलावट विश्वव्यापी समस्या है। ताज्जुब की बात यह है कि मिलावट रूपी संक्रमण को रोकने के लिए सरकार, अदालत और स्वयंसेवी संस्थाएं समय समय पर क़दम उठाते रहे हैं, इसके बावजूद यह समस्या घटने के बजाय बढ़ती जा रही है लेकिन जो आम आदमी मिलावट का सबसे ज़्यादा शिकार है, वह आगे नहीं आता। इसका फायदा उठा कर मिलावटबाज़ अपना धंधा चमकाते रहते हैं। विडंबना यह है कि तमाम तरह की समस्याओं पर आंदोलन और भारत बंद के आहवान किए जाते रहे हैं, लेकिन सीधे सेहत से ताल्लुक़ रखने वाली मिलावट की समस्या के ख़िलाफ़ कोई देशव्यापी आंदोलन आज तक नहीं हुआ। जैसे भ्रष्टाचार धीरे-धीरे शिष्टाचार बन गया है, उसी तरह मिलावट भी ज़िन्दगी का एक हिस्सा बन गया है और लोग इसे लेकर सहज हो चुके हैं इसलिए आंदोलन की ज़रूरत है।

मिलावट की वजह से सबसे बड़ी समस्या लगातार बीमारियों का बढ़ना और कालाबाज़ारी है। मोटापे की समस्या विकसित देशों की तरह भारत में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। जब सर्वोच्च न्यायालय ने दूध में की जा रही मिलावट का स्वत: संज्ञान लेकर स्वामी सच्चिदानंद तीरथ की याचिका को निपटाते हुए इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए थे, तब भी एक आशा जगी थी कि मिलावट में कुछ कमी आएगी। यों तीन वर्ष पूर्व लोकसभा में सरकार द्वारा यह बताया गया था कि देश में बिकने वाला अड़सठ प्रतिशत दूध भारत के खाद्य नियामक द्वारा निर्धारित मानक पर खरा नहीं उतरता। इससे इस बात की पुष्टि हुई कि भारत के करोड़ों लोग दूध के नाम पर मिलावटी रसायन युक्त दूध पीते हैं, जो कई तरह की बीमारियों का कारण बन रहा है।

इसी तरह विज्ञान एवं पर्यावरण केन्द्र ने पास्ता, पित्जा-बर्गर, बन्स ब्रैड, और अन्य फास्ट फूड (जंक फूड) में मिलावट की बात कही है। लेकिन इसका सिलसिला थमा नहीं दिख रहा। आज भी शीतल पेय उत्पादों में चीनी और खतरनाक कीटनाशकों की मात्रा तय मानक से अधिक पाई जाती है। गौरतलब है कि तय मानक वाले पेय उत्पादों को पीने से मोटापा, कैंसर और दूसरी अनेक बीमारियां होने का ख़तरा बराबर बना रहता है। ऐसे में जंग या डिब्बाबंद खाने और ठंडे पेयों से दूर रहना ही समझदारी है।

दुनिया के कई देशों में मोटापे, मधुमेह, कैंसर और दिल की बढ़ती समस्याओं के मद्देनज़र वसा, मीठे पेय पदार्थों, जंक फूड आदि पर टैक्स लगाने शुरू कर दिए गए हैं। इस क़दम से उन देशों में सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। भारत में भी ऐसे कठोर क़दम उठाने की ज़रूरत है। हो सकता है इससे बहुराष्ट्रीय कंपनियां कुछ शोरगुल मचाएं और सरकार को इसके ग़लत परिणाम के लिए दबाव बनाएं। लेकिन देशहित में केन्द्र सरकार को ऐसे क़दम हर हाल में बिना किसी देरी के उठाने चाहिए। ब्रिटेन, अमेरिका, डेनमार्क और दक्षिण अफ्रीका सहित अगर तमाम दुनिया के देश डिब्बाबंद खाद्य, शक्कर वाले पेय पदार्थों पर टैक्स लगा कर ऐसे खाद्य से जनता की पहुंच से दूर करने के लिए निर्णय ले सकती हैं तो भारत क्यों नहीं। जबकि भारत में लगभग सात करोड़ लोग मधुमेह के शिकार हैं। दुनियाभर में दो करोड़ से ज़्यादा बच्चे मोटापे की समस्या से जूझ रहे हैं। इसी तरह भारत में हृदयाघात और कैंसर की बीमारी से करोड़ों लोग ग्रस्त हैं

भारत सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय लोगों के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित तो दिखता है, लेकिन जिन पेयों और खाद्यों से बीमारियां बढ़ रही हैं, उन पर प्रतिबंध नहीं लगा पाता है। ऐसे में, आम लोगों की सेहत को बेहतर बनाए जाने की कोशिशें बेकार साबित हो रही हैं। ज़रूरत इस बात की है कि जल्द से जल्द मिलावटी और सेहत के लिए अभिशाप साबित हो चुके पेयों और खाद्यों को काली सूची में डाल कर सरकार इन्हें प्रतिबंधित करे। दरअसल, देश का लचीला क़ानून बहुराष्ट्रीय और देशी कंपनियों की मनमानी करने की ढिलाई दे देता है। यही वजह है कि ये कंपनियां जंक फूड, शीतल पेयों में निर्धारित मानक से ज़्यादा कीटनाशक, चीनी और नमक मिलाकर लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करती रही हैं। केरल सरकार ने फैट टैक्स लगाकर डिब्बाबंद खाने को महंगा कर दिया था। इससे जहां इसकी बिक्री तो घटी, लेकिन लोगों को एक बात समझ में आ गई कि डिब्बाबंद खाना उनकी सेहत के लिए मुफीद नहीं है। ❑❑

## केसीआर की जगह लेंगे केटीआर

छह महीने बाद केटीआर अपना 45वां जन्मदिन मनाने वाले हैं, लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि उनके पापा उन्हें बर्थडे से पहली बहुत बड़ा गिफ्ट देने वाले हैं। एक ऐसा गिफ्ट जिसे पाने की ख्वाहिश राजनीति में आने वाले हर व्यक्ति की होती है, लेकिन उसे हासिल कर पाना सबके लिए मुमकिन नहीं होता। केटीआर यानि केटी रामाराव तेलंगाना में अपने पिता के. चन्द्रशेखर राव (केसीआर) की तर्ज़ पर अपने शॉर्ट नेम से ही मशहूर है। फिलवक़्त वे अपने पिता की सरकार में मंत्री हैं, लेकिन एक ऐसे मंत्री, जिसका रुतबा केसीआर से भी कहीं ज़्यादा है। सरकार और पार्टी के वे ही सर्वेसर्वा माने जाते हैं। राजनीतिक गलियारों में कहा जाता है कि लोगबाग केसीआर के मुक़ाबले केटीआर को ही खुश रखने में अपनी तरक्क़ी देखते हैं। अब ऐसी चर्चा है कि अगले कुछ माह में केसीआर अपने बेटे केटीआर को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप सकते हैं। केटीआर अपने पिता के इकलौते पुत्र हैं। केटीआर की एक बहन हैं। वह भी राजनीति में हैं। 2014से 2019 के बीच वे लोकसभा सदस्य थीं। केटीआर की कहानी भी हर उस बड़े राजनीतिक परिवार जैसी है, जहां पिता बेटे को राजनीति से दूर रहकन अपनी पढ़ाई लिखाई पर जोर देने को कहता है। हैदराबाद और पुणे की नामचीन शिक्षण संस्थाओं में पढ़ाई करने के बाद केटीआर आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका चले गए। वहां सिटी यूनिवर्सिटी आफ न्यूयार्क से एमबीए की डिग्री ली। वर्ष 2001 से 2006 के बीच वहीं एक बड़ी कंपनी में नौकरी भी की। 2006 में जब केसीआर यूपीए सरकार से अलग होकर लोकसभा का उपचुनाव लड़ रहे थे, केटीआर ने वापस आकर अपने पिता का चुनाव प्रबंधन संभाला। यहीं से उनकी राजनीति में दस्तक मान ली गई। पिता के चुनाव प्रबंधन की कमान संभालने के बाद 2009 में वे पहली बार विधानसभा चुनाव लड़े। तब तेलंगाना आंध्र प्रदेश का ही हिस्सा था। उन्हें पहले ही चुनाव में जीत मिल गई। 2014 में तेलंगाना राज्य के गठन के बाद हुए विधानसभा के चुनाव में उनके पिता की पार्टी को बहुमत मिला और उनके पिता राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने। उनकी सरकार में केटीआर मंत्री बने। 2018 में राज्य विधानसभा के दूसरे चुनाव में भी केटीआर ने जीत दर्ज की और पिता की सरकार में मंत्री हैं।

## ख़ास ख़बरें

### नीदरलैंड में लॉकडाउन के ख़िलाफ़ हिंसा

एम्सटर्डम : विश्व में संक्रमितों की संख्या 10 करोड़ पार होकर 10.09 करोड़ से अधिक हो गई है, वहीं मृतक संख्या भी 21.69 लाख पार हो गई। इस बीच, नीदरलैंड में लॉकडाउन के विरोध में हिंसक घटनाएं दर्ज हो रही हैं। डच सरकार ने कोरोना वायरस के नए संस्करण को रोकने के लिए लॉकडाउन लगाया है जिसके ख़िलाफ़ प्रदर्शन जारी हैं लगातान तीन दिनों में कर्फ्यू के दौरान हिंसा भी हुई।

### नस्लवाद ख़त्म करने के लिए बाइडेन ने दिए आदेश

वाशिंगटन : राष्ट्रपति जो बाइडेन ने देश में नस्लभेद को खत्म करने और सभी को एक समान मानने संबंधी आदेशों पर हस्ताक्षर किए हैं। ये आदेश उन वादों का हिस्सा है जो बाइडेन ने अपने चुनाव के दौरान जनता से किए थे।

बाइडेन ने अपने आदेश में सभी संघीय एजेंसियों से नस्लभेद खत्म करने को कहा है।

### रूस में एटमी हथियारों की संधि 5 वर्ष तक आगे बढ़ाने की मंज़ूरी

मास्को : रूसी की संसद के निचले सदन (डयूमा) ने परमाणु हथियार नियंत्रण संधि 'स्टार्ट' को समझौता खत्म होने से पहले ही पांच वर्ष तक आगे बढ़ाने की मंज़ूरी दे दी है।

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की रूसी राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन के साथ हुई फोन वार्ता के बाद डयूमा ने हथियारों को कम करने वाली इस संधि को बढ़ाने के लिए सर्वसम्मति से मंज़ूरी दी।

### आस्ट्रेलिया : झाड़ियों में मिला 18 दिन से लापता शख़्स, डैम का पानी पीकर बचा

सिडनी : आस्ट्रेलिया के बुशलैंड (झाड़ियों वाले इलाक़े) में 18 दिन पहले लापता हुए शख़्स का पता चल गया है। बचाव दल के अधिकारियों ने बताया कि रॉबर्ट वेबर नाम का यह शख़्स बांध का पानी पीकर और मशरूम खाकर ज़िन्दा रहा।

क्वींसलैंड पुलिस का कहना है कि एक अनजान रास्ते पर वेबर की गाड़ी फंस गई थी, जिसके बाद वह रास्ता भटक गया। 24 जनवरी को स्थानीय नेता टोनी पेरेट और उनकी पत्नी मिशेल को वह सड़क किनारे बैठे मिला। वेबर फिलहाल कुछ बताने की स्थिति में नहीं हैं। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

# हुक़ूक़ुल इबाद क़ुरआन करीम की रोशनी में

**मौलाना मुफ्ती मो॰ शफीह ( रह॰ )**

''और बन्दगी करो अल्लाह की और शरीक न करो, उसका किसी को और मां-बाप के साथ नेकी करो और करावत वालों के साथ और यतीमों और फक़ीरों और अपने निकट जाने पहचाने तथा अजनबी और पास बैठने वालो और मुसाफिर के साथ और अपने हाथ के माल गुलाम बांदियों के साथ, बेशक अल्लाह को पसंद नहीं आता इतराने वाला, बड़ाई करने वाला जो कि बुख़्ल करते हैं और सिखाते हैं लोगों को बुख़्ल और छुपाते हैं जो उनको दिया अल्लाह ने अपने फज़्ल से और तैयार कर रखा है, हमने काफ़िरों के लिए अज़ाब ज़िल्लत का और वह लोग जो कि ख़र्च करते हैं अपने माल लोगों के दिखाने को और ईमान नहीं लाते, अल्लाह पर और न क़यामत के दिन पर और जिसका साथी हुआ शैतान तो वह बहुत बुरा साथी है।''

सूरह निसा की तफ्सीर में आप देखते आए हैं कि इस सूरह में हुकूकुल इबाद का अधिक अहतमाम किया गया है, शुरू सूरह से यहां तक आम इंसानी हुकूक़ की महत्ता का अजमाली तज़करा फरमाने के बाद यतीमों और औरतों के हुकूक़ का अहतमाम और इनमें कोताही की सज़ा, वईद और इस दुनिया में जो उनकी दो सन्फे ज़ईफ यानि बच्चों और औरतों के साथ जुल्म र-वाँ रखा गया और ज़ालिमाना रस्में अख़्तियार की गयीं इनकी इस्लाम का और फिर विरासत के हुकूक़ का बयान है इसके बाद वाल्दैन और दूसरे रिश्तेदारों और संबंधियों और पड़ौसियों और आम इंसानों के हुकूक़ का कुछ तफ्सीली बयान आ रहा है और चूंकि इन हुकूक को आला सबील अल कमाल वही शख़्स अदा कर सकता है जो अल्लाह तआला और रसूल (सल्ल॰) और क़यामत के साथ अकीदा ठीक रखता हो यानि बुख़्ल, किब्र और रिया से भी बचता हो, इसलिए कि यह मामले भी अदाए हुकूक़ में मानह होते हैं इसलिए इन आयतों में तौहीद और तरग़ीब व तरहीब के कुछ मज़ामीन इरशाद फरमाए और शिर्क, इन्कार क़यामत असयाने रसूल (सल्ल॰) और बुख़्ल इत्यादि अख़्लाके ज़मीमा की निन्दा भी ज़िक्र फरमायी।

**खुलासा-ए-तफ्सीर**

''और तुम अल्लाह की इबादत

**बेशक अल्लाह तआला ऐसे व्यक्तियों से मोहब्बत नहीं रखते जो दिल में अपने को बड़ा समझते हैं जुबान से शेख़ी की बातें करते हों जो कि बुख़्ल करते हों और दूसरे लोगों को भी बुख़्ल की तालीम करते हो चाहे जुबान से या इस तरह से कि इनको देख कर दूसरे यही तालीम पाते हैं ) और वह इस चीज़ को पोशीदा रखते हों , जो अल्लाह तआला ने इनको अपने फज़्ल से दी है।**

अख़्तियार करो (इसमें तौहीद भी आ गयी) और इसके साथ किसी चीज़ को (चाहे वह इंसान हो या ग़ैर इंसान इबादत में या उनकी ख़ास सिफात में, एतकाद में) शरीक़ मत करो। और अपने वाल्दैन (मां- बाप) के साथ अच्छा मामला और और दूसरे अहले करावत के साथ भी और यतीमों के साथ भी और ग़रीब गुरबां के साथ भी और पास वाले पड़ौसी के साथ भी और दूर वाले पड़ौसी के साथ भी और हम मजालिस के साथ भी (चाहे वह मजालिस पुरानी दायमी हो जैसे लम्बे सफर की रिफाक़त और किसी मबाह काम में शिरकत या आरज़ी हो जैसे सफर कसीर या इत्तेफाक़ी जल्से में शिरकत) और राहगीर के साथ भी (चाहे वह तुम्हारा ख़ास मेहमान हो या न हो) और गुलाम लौंडियों के साथ भी जो शरअन तुम्हारे मालिकाना कब्ज़े में हैं। ग़रज़ इन सब से खुश मामलगी करो, जिसकी तफ्सील शरअ ने दूसरे मौक़ों पर बतला दी है और जो लोग इन हुकूक़ को अदा नहीं करते अक्सर इसके कई कारण हैं या तो इनके मिजाज़ में तकब्बुर है कि किसी को ख़ातिर में नहीं लाते और किसी की तरफ अल्तफात ही नहीं करते और या इनकी तबिअत में बुख़्ल ग़ालिब है कि किसी को देते दिलाते जान निकलती है और या इनको रसूल अल्लाह (सल्ल॰) के अहकाम को और अदाए हुकूक के सवाब के वादों को और इतलाफे हुकूक़ के अज़ाब वईदों को सही नहीं समझते और यह कुफ्र है और या इनकी आदत नुमाइश और नाम व नमूद की है इसलिए जहां नमूद हो वहां देते - दिलाते हैं यानि हक़ न हो और जहां नमूद न हो, वहां हिम्मत नहीं होती चाहे हक़ हो और या उनको सिरे से ख़ुदा तआला ही के साथ अक़ीदा नहीं या वह क़यामत के क़ायल नहीं और यह भी कुफ्र है इसलिए इसी तरतीब से जो इन मामलों का व्यक्तिगत या सामूहिक पालन करते हैं इनका हाल भी सुन लो कि बेशक अल्लाह तआला ऐसे व्यक्तियों से मोहब्बत नहीं रखते जो दिल में अपने को बड़ा समझते हैं जुबान से शेख़ी की बातें करते हों जो कि बुख़्ल करते हों और दूसरे लोगों को भी

बाक़ी पेज 11 पर

## हजरे असवद लगाने में आप सल्ला. का हकीमाना फ़ैसला

काबा की तामीर के दौरान एक अहम मरहला यह आया कि जब हजरे असवद तक दीवारें पहुंचीं तो हजरे असवद को कौन लगाये? इस पर झगड़ा शुरू हो गया, जाहिलों का क़बीला तो था ही, ज़रा ज़रा सी बातों को अपनी अना का मसअला बना दिया जाता कि फ़लाँ क़बीले वालों ने हजरे असवद रखा हमारी बेइज़्ज़ती कर दी, इसी पर तलवारें तन गईं, पाँच छः दिन तक यह मसअला गरमा गरम रहा कि हजरे असवद कौन लगाये? हालांकि ऐसी कोई बड़ी बात तो थी नहीं, तामीर में कोई भी लगा सकता है, मगर इसी में हट धर्मी शुरू हो गई। बिल आख़िर उन में से एक सरदार उमैया बिन अल-मुग़ीरा ने यह कहा कि आख़िर कब तक लड़ते रहोगे, और कहा कि तय करो कल सुबह जो आदमी पहले नम्बर पर मस्जिद में आए उसको हम अपना हकम बना लेंगे, जो वह कहे उसका फ़ैसला हम सब तस्लीम करेंगे, लोगों ने कहा यह राय सब से बेहतर है। अब सुबह का इंतेज़ार होने लगा, चुनान्चे सुबह देखा कि सब से पहले पैग़म्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाए तो देखते ही सब के सब कहने लगे कि हाँ यह आदमी सच्चा और अमीन है, हम उन के फ़ैसले पर राज़ी हैं, पैग़म्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाए और मालूम किया कि क्या क़िस्सा है? बतलाया कि यह झगड़ा चल रहा है, आप ने फ़रमाया कि एक चादर ले आओ, चादर लाई गई, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि यहाँ कितने क़बीले हैं? चुनान्चे बतलाया गया, आप ने फ़रमाया कि हर क़बीला अपना एक एक नुमाइन्दा ले आए, जब सब के नुमाइन्दे आ गए, तो हज़रत ने फ़रमाया कि देखो यह हजरे असवद रखा है, अगर आप सब मिलकर मुझे अपना नुमाइन्दा बना दो, तो मैं इस को चादर में रख दूँ, सब ने कहा बहुत अच्छा और आप ने फ़रमाया कि मैंने ख़ुद नहीं बल्कि आप ही की तरफ़ से रखा है, आप ने फ़रमाया कि इस चादर को सब उठा लें तो सब ने पकड़ ली, जब उस जगह पहुंचे जहाँ पर पत्थर लगाना था, तो आप ने फ़रमाया कि अगर आप मुझे इजाज़त दें तो आप ही की तरफ़ से मैं फिर इसको लगा दूँ, सब ने कहा कि बहुत अच्छा, आप ने चादर से उठा कर उसको नसब कर दिया, तो अल्लाह तआला ने आप के ज़रिये से एक बहुत बड़ी लड़ाई ख़त्म करा दी।

## नूरे क़ुरआन

### ( सूरा अल तकवीर नं॰ 81 )

**अनुवाद और व्याख्या : शैख़ुल हिन्द र.अ.**

**और यह कुरआन किसी धिक्कारे हुए शैतान का कलाम नहीं है।**

भला शैतान ऐसी नेकी और परहेज़गारी की बातें क्यों सिखाने लगा जिसमें पूर्ण रूप से आदमी की संतान का लाभ हो और स्वयं उस दुष्ट की बुराई हो।

**फिर तुम किधर चले जा रहे हो।**

अर्थात् जब झूठे, पागलपन, काहिन होने के तमाम आरोप लट गये तो वास्तविक और सच्चाई के अतिरिक्त और क्या रहा। फिर इस प्रकाशमान और साफ रास्ते को छोड़कर किधर बहके चले जा रहे हो।

**यह तो जहान भर के लिए एक उपदेश है।**

क़ुरआन के संबंध में जो शंकायें तुम पैदा करते हो सब ग़लत हैं यदि इसके विषयों और अच्छाई में ध्यान दो तो इसके अतिरिक्त कुछ न मिलेगा कि पूरे संसार के लिए एक सच्चा उपदेश और समाज का पूर्ण संविधान है जिससे उनके इस लोक और परलोक की भलाई बंधी है।

**ऐसे व्यक्ति के लिए जो तुम में से सीधा चलना चाहे।**

अर्थात् विशेष रूप से उनके लिए उपदेश है जो सीधे मार्ग पर चलना चाहते हैं। शत्रुता और टेढ़ापन स्वीकार नहीं करते क्योंकि ऐसे ही लोग इस उपदेश से लाभ उठायेंगे।

रुकू नं॰ 1

**और तुम बिना अल्लाह के चाहे के जो कुल संसार का पालनहार है कुछ नहीं चाह सकते।**

अर्थात् कुरान वास्तव में स्वयं एक उपदेश है लेकिन उसका प्रभाव अल्लाह की इच्छा पर आधारित है जो कुछ व्यक्तियों के लिए होता है और कुछ के लिए अल्लाह की किसी तात्विकता से उनकी बुरी प्रकृति के कारण नहीं होता।

### ( सूरा इन फितार नं॰ 82 )

यह सूरा मक्का में उतरी इसमें 19 आयतें हैं

**प्रारंभ करता हूं मैं अल्लाह के नाम से जो असीम कृपालु महादयालु है।**

**जब आसमान फट जाये और जब सितारे झड़ पड़े और जब दरिया उबल निकलें।**

अर्थात् समंदर का पानी ज़मीन पर ज़ोर करे अन्त में खारे और मीठे सब पानी मिल जायें।

**और जब कब्रें उथल-पुथल कर दी जायें।**

अर्थात् जो वस्तु ज़मीन की तह में थी ऊपर आ जाये और मुर्दे कब्रों से निकाले जायें।

**प्रत्येक व्यक्ति अपने अगले और पिछले कार्यों को जान लेगा।**

अर्थात् जो भले बुरे काम किये या नहीं किए, प्रारंभिक जीवन में किए या अन्तिम उम्र में उनका प्रभाव अपने पीछे छोड़ा या नहीं छोड़ा सब उस समय सामने आ जायेंगे।

**ऐ इंसान तुझको किस वस्तु ने तेरे ऐसे करीम पालनहार से भूल में डाल रखा है।**

अर्थात् वह रब कृपालु क्या इसका हक़दार था कि तू अपनी मूर्खता और दुष्टता से उसके धैर्य पर घमंडी होकर अवज्ञायें करता रहे और उसकी कृपादृष्टि का उत्तर इंकार और उद्दंडता से दे। उसकी कृपा देखकर तो अधिक लज्जित होना और धैर्य के गुस्से से अधिक डरना चाहिए था। निःसंदेह वह दयालु है लेकिन बदला लेने वाला और तत्वज्ञानी भी है। फिर यह घमंड और धोखा नहीं तो और क्या होगा कि उसके एक गुण को लेकर दूसरे गुणों से आंख बंद कर ली जाये।

## नअ्त शरीफ़

दिलों के गुलशन महक रहे हैं ये क़ैफ़ क्यों आज आ रहे हैं
कुछ ऐसा महसूस हो रहा है हुज़ूर तशरीफ़ ला रहे हैं
कहां का मंसब कहां की दौलत क़सम खुदा की ये है हक़ीक़त
जिन्हें बुलाया है मुस्तफ़ा ने वही मदीना को जो रहे हैं
हबीबे दावर ग़रीब परवर रसूले अकरम करम के पैकर
किसी को दर पर बुला रहे हैं किसी के ख़्वाबों में आ रहे हैं
न पास पी हो तो सूना सावन वो जिस पर राज़ी वही सुहागन
जिन्होंने थामा नबी का दामन उन्हीं के घर जगमगा रहे हैं
गदा की औक़ात है ही कितनी, हक़ीक़तन है ये बात इतनी
खुदा है देता नबी का सदक़ा नबी का सदक़ा ही खा रहे हैं
नवाज़िशों पे नवाज़िशें हैं इनायतों पे इनायते हैं
नबी की नअ्तें सुना सुनाकर हम अपनी क़िस्मत जगा रहे हैं
बनेगा जाने का फिर बहाना कहेगा आकर कोई दीवाना
चलो नियाज़ी तुम्हीं मदीने, मदीने आक़ा बुला रहे हैं।

# आख़िर नेहरू से इतनी नफ़रत क्यों?

**आकार पटेल**

मेरी किताब के लिए मेरा साक्षत्कार लिया जा रहा है तथा मुझे इससे ग़ैर संबंधित एक सवाल पूछा गया कि ''हिन्दूत्व नेहरू से इतनी नफ़रत क्यों करता है?'' यह एक दिलचस्प सवाल है और इसके जवाब के दो हिस्से हैं। इसे जानने के लिए हमें पहले यह समझना होगा कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू क्या थे तथा वे क्या चाहते थे? आज़ादी से पहले पंडित नेहरू ने कई रचनाएं लिखीं जिसके माध्यम से उन्होंने खुद को भारत की उस सभ्यता की इकाई के रूप में सारेखित किया जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आर.एस.एस.) भी स्वीकार करता हैं उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता में अपनी उत्पत्ति के लिए आधुनिक राष्ट्र का पता लगाया।

कुछ वर्ष पहले उन्हाहेंने विश्व इतिहास की झलकियां लिखीं थीं और केवल 15 या इतने वर्ष पहले उन्होंने 'भारत की खोज' लिखा था लेकिन यह स्वीकार करते हुए कि भारत प्राचीन था, नेहरू ने इसे आधुनिक दुनिया के लिए सारेखित करने की मांग भी की और वह युग जिसका वह हिस्सा थे भविष्य में उन्होंने सभी मानव जाति के लिए देखा। उस छोर तक उन्होंने राज्य को आधुनिक बनाने के लिए एक साधन के रूप में इस्तेमाल किया।

नेहरू जी ने दो चीज़ों पर अपनी रणनीति आधारित की : एक भारी उद्योग तथा दूसरी उच्च शिक्षा।

भारत के पास सीमित साधन थे मगर इन दोनों को प्राथमिकता दी जानी थी। आप यह तर्क देंगे कि क्या रणनीति अच्छी, बुरी या उदासीन थी मगर यह कहना मुश्किल होगा कि जो उन्होंने नहीं किया उसे करने की कोशिश की थी। उन्होंने संस्थानों का निर्माण करना शुरू किया जिनमें से कुछ को आज 'नवरत्नों' के नाम से बुलाया जाता है मगर तब कुछ भी नहीं था और निर्माण की आवश्यकता थी। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि. (1964), तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (1956), भारतीय इस्पात प्राधिकरण (1954), हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लि. (1964), इंडियन ऑयल कापोरेशन (1959), इसरो (पूर्व में आई.एन.सी.ओ.एस.पी.ए.आर.) (1962), परमाणु ऊर्जा विभाग (1954), भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र (1954), फिर नेहरू ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (1951), भारतीय प्रबंधन संस्थान (1961), राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान (1961), साहित्य अकादमी (1954), की स्थापना की।

यह सूचि अनवरत है। इन सभी की स्थापना आखिर क्यों की गई? वे स्थापित किए गए क्योंकि वे ऐसे साधन हैं जिनके माध्यम से नेहरू ने भारत को आधुनिक बनाया। उन्हें एक पूर्व आधुनिक अर्थव्यवस्था विरासत में मिली जहां उत्पादन का अधिकांश हिस्सा कृषि में पड़ा था और उस कृषि का प्रबंधन एक किसान द्वारा किया जा रहा था, जिसकी खेती के साधन हज़ार सालों में बहुत कम बदले।

नेहरू को विरासत में एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था नहीं मिली थी।उन्हें यह पता लगाना था कि भारत को वहां तक कैसे ले जाया जाए। समस्या यह है कि नेहरू की तुलना करने में हमारे प्रधानमंत्री सहित हिन्दुत्व में किसी के पास कोई भी दृष्टि बुरी या अच्छी उदासीन नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी केवल हमें 'पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था' जैसे बयान दे सकते हैं लेकिन वह कुछ नहीं कहते क्योंकि वह खुद आप ही नहीं जानते कि वहां तक पहुंचने के लिए यहां पर क्या करना है?

पंडित नेहरू ने कहा, ''भारी उद्योग तथा उच्च शिक्षा।'' मोदी क्या करते हैं? इसका उत्तर आपके लिए ढूंढ पाना मुश्किल है क्योंकि इसका उत्तर है ही नहीं। यहीं पहला कारण है कि भाजपा और हिन्दुत्व नेहरू से ईर्ष्या करते हैं।

दूसरा कारण यह है कि नेहरू एक धोखाधड़ी करने वाले राष्ट्रवादी नेता नहीं थे वह असली थे। उन्होंने न केवल चीन का नाम लिया बल्कि उन्होंने इसका मुक़ाबला भी किया। नेहरू हार गए क्योंकि नेहरू ने युद्ध किया क्योंकि वह अपनी कीमती भारतीय भूमि को किसी के आगे आत्मसमर्पण करने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे।

14 नवंबर 2019 को विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने रामनाथ गोयंका व्याख्यान में कहा कि ''नेहरू को चाऊ एनलाई की 1960 की भारत यत्रा के दौरान सीमा विवाद को लेकर चाऊ का प्रस्ताव मान लेना चाहिए था?'' यह प्रस्ताव क्या था? प्रस्ताव यह था कि भारत कराकोरम रेंज को सीमा के रूप में स्वीकार कर ले। वास्तव में आज यह वह स्थिति है जहां निरंतर रेखा आज मौजूद है। मगर नेहरू को यह स्वीकार्य नहीं था वे सीमा को तिब्बत तक आगे बढ़ाना चाहते थे और इसके लिए वह युद्ध के लिए भी तैयार थे। वे हार गए मगर उन्होंने भारतीय दावे को कभी नहीं छोड़ा।

यह मोदी के विपरीत है जिन्होंने न केवल भारतीय दावे को छोड़ा बल्कि डर के मारे अपने दुश्मन का नाम लेने के लिए तैयार भी नहीं। नेहरू नाम का इस्तेमाल आज के समय में बहुत कम किया जाता है। हम नहीं जानते कि उन्होंने क्या क्या किया है? हमने उनकी सोच को सरल शब्दों में नहीं समझाया है। नेहरू न केवल उन सबसे बहुत बेहतर हैं जो उनके बाद आए जिन्हें हम विशेष तौर पर आर्थिक पतन और राष्ट्रीय सुरक्षा विफलता के दौर में देखते हैं लेकिन नेहरू आधुनिकता के लिए एक आदर्श हैं। इस वर्तमान में कितने प्रधानमंत्री जिसमें वर्तमान मोदी भी शामिल हैं उनके बारे में क्या हम ऐसा कह पाएंगे? ❑❑

# कोविड से जंग को अमेरिकी अंदाज़

**राजीव रंजन तिवारी**

भारत में कोरोना से बचाव के लिए युद्धस्तर पर अभियान शुरू हो गया हैं फिर भी सतर्कता ज़रूरी है। इसी क्रम में दुनिया के सबसे मज़बूत देश अमेरिका के अंदाज़ को समझना ज़रूरी है। अमेरिका में कोरोना से लड़ने के लिए क्या क्या हो रहा है, यह भी परखना चाहिए। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 1.9 लाख करोड़ डॉलर की योजना पेश की हे। इसे वैक्सीन के प्रसार और महामारी क कारण आर्थिक संकट से जूझ रहे लोगों को राहत देने में ख़र्च किया जाएगा। इस योजना को अमेरिकन रेस्क्यू प्लान कहा जा रहा है। जो बाइडेन ने अपने 100 दिन के कार्यकाल में 10 करोड़ वैक्सीन लगाने का लक्ष्य तय किया है और यह प्रस्ताव उसे पूराकरने की दिशा में अहम भूमिका निभाएगा। इसके साथ ही वसबंत का मौसम आने तक अमेरिका के सारे स्कूलों को खोलने की दिशा में भी अहम प्रगति इसी योजना का हिस्सा है। साथ ही अर्थव्यवस्था को स्थिरता देने के लिए दूसरे दौर की मदद और स्वास्थ्य सेवाओं को महामारी से जूझने में ज़्यादा सक्षम बनाना भी योजना में शामिल हैं बाइडेन ने देश को संबोधित करते हुए कहा कि इस समय ज़्यादा सक्षम बनाना भी योजना में शामिल हैं बाइडेन ने देश को संबोधित करते हुए कहा कि इस वक्त इसके लिए काम करना न सिर्फ आर्थिक रूप से अनिवार्यता है बल्कि यह हमारी नैतिक ज़िम्मेदारी भी है इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि उनकी योजना पर अमल इतना आसान नहीं होगा।

जो बाइडेन ने ज़्यादातर अमेरिकी लोगों को 1400 डॉलर का चेक देने का प्रस्ताव रखा है। यह हाल ही में प्रस्तावित 600 डॉलर के चेक से अलग होगा यानि कुल मिलाकर लोगों को 2000 डॉलर की रक़म मिलेगी जिसकी मांग बाइडेन कर रहे हैं। इसके साथ ही बेरोज़गारी भत्ते को तात्कालक रूप से थोड़ा बढ़ाया जाएगा। साथ ही नौकरी से हटाने और प्रतिष्ठानों के समय से पहले बंद करने पर लगी रोक सितंबर तक के लिए बढ़ाई जाएगी। दिसंबर में प्रस्तावित डेमोक्रेटिक नीति में सुझाए रास्तों पर चलते हुए देश में न्यूनतम मज़दूरी 15 डॉलर प्रति घंटे की जा रही है और साथ ही कामगारों के लिए वेतन सही छुट्टी की संख्या और बच्चों वाले परिवारों के लिए टैक्स में छूट भी बढ़ेगी। महिलाओं के लिए काम पर जाना आसान होगा जिससे अर्थव्यवस्था के सुधार में मदद मिलेगी। आर्थिक रूप से लुभावना दिख रहा प्रस्ताव राजनीतिक रूप से कैसे बढ़ेगा फिलहाल यह साफ नहीं है।

संयुक्त बयान में संसद के निचले सदन की स्पीकर नैन्सी पेलोसी और सीनेट में डेमोक्रेटिक नेता चक शुमर ने बाइडेर की उदार प्राथमिकताओं की तारीफ की है उन्होंने यह भी कहा है कि वे इसे संसद में तेज़ी से पास कराने के लिए काम करेंगे। हालांकि संसद के दोनों सदनों में डेमोक्रेटिक पार्टी के पास मामूली बढ़त है और रिपब्लिकन पार्टी कई मुद्दों पर उन्हें घेरने की कोशिश करेगी, इनमें न्यूनतम मजदूरी को बढ़ाने से लेकर राज्यों को ज़्यादा ध न देने जैसे मुद्दे हैं। इसके साथ ही इसमें व्यापार को दायित्व से मिलने वाली सुरक्षा को बढ़ाने जैसी उनकी प्राथमिकताओं को शामिल कराना भी होगा।

टैक्सास को रिपब्लिकन सीनेटर जॉन कॉर्निन ने टवीट किया है कि याद रखिए कि दोनों दलों ने 900 अरब डॉलर के राहत बिल को महज़

बाक़ी पेज 11 पर

# कोरोना वैक्सीन कितने वर्ष कारगर होगी

**अमित गुप्ता**

कोरोना वायरस को हराने के लिए पूरी दुनिया अपने-अपने स्तर पर प्रयास कर रही है। भारत में भी दो वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंज़ूरी मिल गई है। लेकिन इन सबके बीच वायरस के स्ट्रेन में आ रहे बदलाव ने सबकी चिंताएं बढ़ा दी हैं। अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका और नाइजीरिया में पाए गए स्ट्रेन पर वैक्सीन प्रभावी होगी की नहीं। ऐसे में वैज्ञानिक इस परीक्षण में लगे हुए हैं कि इन नए स्ट्रेन्स पर वैक्सीन का कितना प्रभाव पड़ेगा?

पूरी दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों में कोरोना टीकाकरण शुरू होना सुखद संकेत है। भारत की विशाल आबादी और विविधता के साथ नेपाल समेत अन्य देशों के लिए टीके की आपूर्ति सुनिश्चित कराने के लिए भारत को अलग-अलग क़िस्मों की वैक्सीन को मंज़ूरी देना महत्वपूर्ण है, तभी कम समय में 135 करोड़ लोगों का टीकाकरण संभव हो सकेगा। सुरक्षा और प्रभाव का आंकलन करते हुए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया फाइजर, स्पूतनिक वी और मॉडर्ना की वैक्सीन को भी मंज़ूरी दे सकते हैं। कई सारे ऐसे टीके हैं, जिन्होंने क्लीनिकल ट्रायल के दौरान अपनी प्रभावशीलता साबित की है।

इससे पहले पोलिया ऐसा वायरस था, जिसकी रोकथाम के लिए दुनिया में एक से ज़्यादा वैक्सीन का इस्तेमाल किया गया। इसमें एक ओरल पोलियो वैक्सीन और दूसरी इनएक्टिवेटेड पोलियोवायरस वैक्सीन शामिल थी। ओरल वैक्सीन भी अलग-अलग किस्मों की इस्तेमाल हुई। आईपीवी तीनों तरह के पोलियो वायरस से सुरक्षा देती है। सुरक्षा मानकों का ध्यान रखते हुए भारत या दुनिया के अन्य हिस्सों में लोगों को अलग-अलग कोविड-19 वैक्सीन लगाने का कोई नुकसान नहीं है। सारी उपलब्ध वैक्सीन का प्रभाव 60 प्रतिशत से ज़्यादा पाया गया हैं यह कोरोना के संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए पर्याप्त है। वैक्सीन को लेकन किस में कितनी इम्यूनिटी रहती है यह लोगों की प्रोटेक्टिव एंटीबॉडी के स्तर पर निर्भर करता है। यही कारण है कि हमेशा किसी वैक्सीन के क्लीनिकल ट्रायल के दौरान बड़ी संख्या में अलग-अलग आयु वर्ग के वालंटियर को शामिल करने की सलाह दी जाती है। इससे यह पता चलता है कि कौन सी वैक्सीन किस आयु वर्ग के लोगों पर कैसा असर डालेगी। लिहाज़ा ऐसी वैक्सीन के भारत में टीकाकरण महत्वपूर्ण है, जिनका क्लीनिकल ट्रायल भारत में हुआ हो। ऑक्सफोर्ड-एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन का भारत में सीमित स्तर पर ही सही लेकिन ट्रायल हुआ है। भारत

बाक़ी पेज 11 पर

# 10 मीटर एयर पिस्टल में वर्ल्ड नंबर-2 मनु भाकर

# ओलम्पिक स्थगित होने से निराश हो गई थी, उबरने में समय लगा

**यूथ ओलंपिक चैम्पियन शूटर मनु भाकर टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए पदक की बड़ी उम्मीद है। 2019 वर्ल्ड कप फाइनल में गोल्ड जीतने के बाद दुनिया की नंबर दो खिलाड़ी मनु किस बड़े इवेंट में नहीं उतरी हैं। नेशनल ट्रायल से पहले 18 वर्ष की मनु मप्र की स्टेट शूटिंग एकेडमी में ट्रेनिंग में व्यत रही। उन्होंने बताया कि ओलंपिक स्थगित होने के बाद उन्हें काफी बुरा लगा था और वे इससे उबरने के लिए कोशिश कर रही थीं। उन्होंने ओलंपिक की तैयारी, लॉकडाउन के दौरान मानसिक स्थिति और प्रतिद्वंद्वियों के बारे में बातचीत की, पेश है इस बातचीत के प्रमुख अंश।**

**प्रश्नः**- तैयारी कैसी चल रही है? घर में भी प्रेक्टिस की और दिल्ली में कैंप में भी इसका कितना असर रहा?

**उत्तरः**- तैयारियां तो काफी अच्छी चल रही हैं। काफी समय बाद शूटिंग शुरू की है तो धीरे धीरे पेस आ रहा है। बीच में भी ट्रेनिंग करना काफी ज़रूरी था, जिससे सब कुछ मेंटेन हो सके। इसलिए थोड़ी बहुत ट्रेनिंग चलती रही। कैंप में टीम के साथ वहां के माहौल में ट्रेनिंग करने का मैं काफी समय से इंतज़ार कर रही थी, तो काफी अच्छा लगा।

**प्रश्नः**- घर पर ट्रेनिंग और शूटिंग रेंज में ट्रेनिंग करने में कितना अंतर होता है?

**उत्तरः**- माहौल का काफी फर्क होता है। जब हम रेंज पर ट्रेनिंग करते हैं तो हमारे साथी होते हैं। कई बार हम उन्हें देखकर भी सीखते हैं। अगर हम नहीं भी देखते हैं तो कम से कम हमें कॉम्पिटिटर वाली फीजिंग आती है, जो हमें मोटिवेट करती रहती है।

**प्रश्नः**- शूटिंग में मनोस्थिति का महत्व होता है। लॉकडाउन के दौरान क्या स्थिति थी?

**उत्तरः**- जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो ओलंपिक तक का प्लान बना लिया था। ओलंपिक के पोस्टपोन होने से काफी बुरा लगा था। उम्मीद छोड़ दी थी कि अब कुछ नहीं हो सकता। उबरने में एक दो सप्ताह लग गए थे। जब लक्ष्य होता है तब ही अच्छी तरह से ट्रेनिंग कर पाते हैं। लक्ष्य सामने न होने से अंधों की तरह चलते हैं। कहीं रास्ता नहीं दिखता। ट्रेनिंग ही करते रहते हैं।

**प्रश्नः**- ट्रायल शुरू हो गए हैं, उसके बाद वर्ल्ड कप भी हैं क्या आप इन्हें ओलम्पिक की तैयारियों

**जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो ओलंपिक तक का प्लान बना लिया था। ओलंपिक के पोस्टपोन होने से काफी बुरा लगा था। उम्मीद छोड़ दी थी कि अब कुछ नहीं हो सकता। उबरने में एक दो सप्ताह लग गए थे। जब लक्ष्य होता है तब ही अच्छी तरह से ट्रेनिंग कर पाते हैं। लक्ष्य सामने न होने से अंधों की तरह चलते हैं।**

के रूप में देखती हैं?

**उत्तरः**- लंबे समय के बाद इंटरनेशनल खेलने को मिलेगा। ट्रायल्स की भी तैयारी चल रही हैं लक्ष्य होगा तो हम और अच्छे से ट्रेनिंग कर सकते हैं। बड़े इवेंट से पहले एक्सपोजर ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि फील भूल चुके हैं, लेकिन दोबारा से रिवाइव करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा टूर्नामेंट खेलने होंगे।

**प्रश्नः**- टूर्नामेंट न हो पाने से प्रतिद्वंदी के बारे में कैसे पता चलेगा? किन देशों से चुनौती?

**उत्तरः**- हमें सिर्फ अपना लेवल बनाए रखने की ज़रूरत है। भारतीय शूटिंग पिछले वर्ष तक लय में थी। हमें अपनी रिदम बनाए रखनी है। चीन, ग्रीस और सर्बिया की चुनौती सबसे ज़्यादा होगी।

**प्रश्नः**- महिला खिलाड़ियों की स्थिति पर क्या राय है? हरियाणा में बढ़ावा मिल रहा है। बाक़ी राज्य कैसे अच्छा कर सकते हैं?

**उत्तरः**- लड़कियों को धीरे-धीरे इवेंट मिल रहे हैं। कुछ वर्ष पहले भी देखें तो शूटिंग में काफी कम लड़कियां होती थीं। काफी जल्द ये चीज़ें बढ़ी हैं। यह देखकर मुझे काफी अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि बेटी बचाओ, पढ़ाओ और जो मुहिम चली हे, उससे फायदा मिल रहा है। सिर्फ शहर ही नहीं, गांव में भी। हरियाणा में भी खेल का अच्छा माहौल है।

**प्रश्नः**- आपने यूपीएससी को लेकर भीा पोस्ट किया था। उसके बारे में भी क्या सोचा था?

**उत्तरः**- मेरा स्ट्रीम पॉलिटिक्स साइंस है। उसमें काफी हद तक यूपीएससी का सिलेबस कवर होता है हम भी कोशिश कर लेंगे।

**प्रश्नः**- खिलाड़ी आजकल राजनीति में भी जा रहे हैं। आपका कोई प्लान? भारतीय राजनीति पर कुछ बोलना चाहेंगी?

**उत्तरः**- अभी आगे का तो कोई प्लान नहीं सोचा है। चीजें दिमाग़ में है। लेकिन अभी सिर्फ शूटिंग से जुड़ी रहना चाहती हूं। भारतीय राजनीति पर कुछ नहीं कहना। ❑❑



# पेट दर्द के अनेक कारण हो सकते है

पेट दर्द सबको समय-समय पर हो जाता है। लक्षणों के आधार पर डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता हो सकती है। आईये जाने क्या-क्या समस्या हो सकती है जिनसे पेट दर्द होता है।

### गैस्ट्रिटिस

भोजन को पचाने में मदद करने वाले तरल में बहुत अधिक एसिड होता है। अगर पेट सुरक्षात्मक बाधा म्यूक्स न हो तो एसिड पेट को नुकसान पहुंचा सकता है परत को काट सकता है। जब इस म्यूक्स की लेयर कम हो जाती है या एसिड स्त्राव (सेक्रीसन) ज़्यादा होता है तो अमाशय की परत में जलन होने लगती है जिसे गैस्ट्रिटिस कहा जाता है। बैक्टीरिया, आईब्रुप्रोफेन, बहुत अधिक शराब, या तनाव जैसे दर्द रिलीवर के नियमित उपयोग द्वारा भी हो सकता है। आप कभी-कभी इसे ओवर द काउंटर एंटासिड या प्रिस्क्रिप्शन दवाओं के साथ इलाज कर सकते हैं।

### पेस्टिक अल्सर

उपरोक्त कारणों से पेट की परत या छोटी आंत के ऊपरी हिस्से में घाव हो सकते हैं। इसका आम कारण बैक्टीरिया है लेकिन एस्पिरीन, आईबुप्रोफेन और अन्य दर्द निवारक दवाओं के दीर्घकालिक उपयोग से भी हो सकता है। धूम्रपान करते हैं या तम्बाकू खाते हैं, उन्हें ये अल्सर अधिक बार मिलता है।

### वायरस या गैस्ट्रिक फ्लू

पेट फ्लू आंतों में एक वायरल संक्रमण है। इससे पतले पानीदार दस्त, ऐंठन या मतली हो सकती है, यह किसी संक्रमित व्यक्ति से हाथ मिलाने या उसके साथ तौलिये आदि सांझा करने या दूषित संक्रमित भोजन के माध्यम से हो सकता है। इसका कोई इलाज नहीं है, केवल लक्षणों का इलाज यथा बुख़ार की दवा निर्जलिकरण डी हाइड्रेशन हेतु जीवन रक्षक घोल ले सकते हैं। या बचाव हेतु हाथ धोना व वस्त्र साझा न करना संक्रमित भोजन से बचना जैसे उपाय कर सकते हैं।

### खाद्य विषाक्ता फूड पाइजनिंग

भोजन में बैक्टीरिया, वायरस और परजीवी इस बीमारी का कारण बनते हैं। फूड पाइजनिंग से दस्त, मतली और उल्टी हो सकती है। यह संक्रमित भोजन खाने से होता है। यह आमतौर पर अपने आप ठीक हो जाता है, लेकिन यदि आप निर्जलित यानि डी हाइड्रेशन से ग्रसित हैं और जीवन रक्षक घोल से ठीक नहीं हो रहे तो तुरंत चिकित्सीय मदद लें चिकित्सक आइ वी फ्लूइड व एंटी बायोटिक दे सकते हैं। अगर किसी को फूड पॉइजनिंग के कोई लक्षण हैं और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं हैं या फिर कमज़ोर प्रतिरक्षा प्रणाली कोम्प्रोमिज्ड इम्युनिअी यथा एच आइ वी या अन्य रोग है तो उसे तुरंत चिकित्सीय सहायता लेनी चाहिए।

### अपेंडीसाइटिस परिशिष्ट

(अपेंडीक्स) एक उंगली के आकार का अंग है जो पेट के निचले दाहिने हिस्से में की शुरूआत में पाया जाता है। यह जानवरों तथा ऊंटों में तो भोजन संग्रह का काम करता है लेकिन मानव में धीरे धीरे सिकुड़ गया है क्योंकि सदियों से मानव शरीर को भोजन भंडारण की ज़रूरत नहीं रही। यह स्पष्ट नहीं है कि यह मानव शरीर में अब क्या करता है, लेकिन जब यह संक्रमित होकर सूजन कर देता है तो फट भी सकता है तब इसे निकालने हेतु ऑपरेशन करना पड़ता है क्योंकि इसके फटने से बैक्टीरिया सारे पेट में फैल सकते हैं। पहले पेरिटोनाइटिस फिर मृत्यु तक हो सकती है। शुरुआत में एंटी बायोटिक व आइ वी फ्लूइड से ठीक हो सकता है लेकिन बार बार होने की शंका होती है।

### गाल स्टोनज

आमतौर पर पित्ताशय की पथरी - उन टयूबों या नलिकाओं को ब्लॉक कर देती हैं जिनके द्वारा बाइल नामक द्रव्य जिगर व अग्न्याशय द्रव्य, पित्ताशय की थैली से छोटी आंत तक पहुंचता है के बीच चलते हैं। आम लक्षण पेट दर्द हैं- मतली, उल्टी बुखार, गहरे रंग का मूत्र और हल्के मटमैले रंग का मल भी हो सकते हैं। पत्थर अक्सर अपने आप निकल सकते हैं लेकिन अगर वे नहीं निकलते तो सर्जरी की आवश्यकता हो सकती है।

### हर्निया - (इन कार्सटरेटिसडहर्निया)

हर्निया तब होता है जब आंतों का एक हिस्सा के पेट की दीवार के माध्यम से स्लाइड करता है। जब यह मुड़ जाता है यानि मरोड़ खा लेता है तो मरोड़ के बाद के हिस्से की रक्त की आपूर्ति से कट जाती है, जिस तरह हर्ट अटैक में हर्ट, यह आपके पेट में गंभीर दर्द पैदा कर सकता है। समस्या को ठीक करने के लिए अक्सर सर्जरी की जल्दी ज़रूरत होती है।

### कब्ज़

सप्ताह में तीन से कम मल त्याग होने पर कब्ज़ होना माना जाता है। व्यायाम, ख़ूब पानी और ऐसे खाद्य पदार्थ जिनमें बहुत सारे फाइबर खाना जो कब्ज़ नहीं होने देते इसमें बचाव कर सकते हैं होते हैं, साबुत अनाज सलाद आदि, मदद कर सकते हैं, कब्ज़ भी पेट दर्द कारणों में से एक हो सकता है।

### अग्न्याशय शोथ

(पेंक्रीएटाइटिस)

ऐसा तब होता है जब अग्न्याशय (पेंक्रीआज) जो शरीर को चीनी की प्रक्रिया में मदद करता है और भोजन को पचाता है, सूजन हो जाता हैं ऊपरी पेट में दर्द हो सकता है जो खाना खाने के बाद बढ़ जाता हैं बुख़ार मतली व उलटी हो सकती है, गंभीर स्थिति में आइफ्लूइड व एंटी बायोटिक से उपचार कियाजाता है। ❑❑

## शेष.... प्रथम पृष्ठ

किया था? मुसलमानों के सैकडों संगठनों ने स्वाधीनता संग्राम में हिन्दुओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंग्रेजों के ख़िलाफ़ संघर्ष किया था। स्वाधीन भारत को आधुनिक और प्रगतिशील बनाने में सभी धर्मों के लोगों का योगदान रहा है। उन्होंने उद्योग, शिक्षा, खेल, संस्कृति और अन्य सभी क्षेत्रों में बड़ी सफलताएं हासिल की हैं और देश का नाम रोशन किया है। क्या वे सब राष्ट्रवादी देशभक्ति नहीं हैं? दूसरी ओर, भागवत यह कहकर संघ की शखाओं में प्रशिक्षित नाथूराम गोडसे का बचाव कर रहे हैं, जिसने गांधी जी की हत्या की थी। हम उन लोगों को क्या कहें जिन्होंने बाबरी मस्जिद को जमींदोज़ किया, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अपराध क़रार दिया है? क्या भागवत यह मानते हैं कि गांधी जी, कलबुर्गी, दाभोलकर, गौरी लंकेश और गोविन्द पंसारे के हत्यारे देशभक्ति थे? क्या वे हिन्दू भी देशभक्त हैं जो अन्य मुल्कों के लिए जासूसी करते पकड़े गए हैं जो तस्करी करते हैं, ब्लैकमार्केटिंग करते हैं? जहां एक ओर आरएसएस, गांधी जी के प्रति समान का भाव रखने का नाटक करता है वहीं उसके प्रचारक और चिंतक और उससे जुड़े कई संगठन खुलेआम नाथूराम गोडसे का महिमामंडन कर रहे हैं। पिछली गांधी जयंती पर बड़ी संख्या में हिन्दुओं ने गोडसे की प्रशंसा करते हुए टवीट किये। साफ है कि आरएसएस के कई चेहरे और मुखौटे हैं। वो एक ही समय में गांध ीजी के प्रति श्रद्धा भी व्यक्त कर सकता है और उस सोच को बढ़ावा भी दे सकता है जिसके कारण बापू की जान गई। ❑❑

## शेष.... हुकूकुल इबाद....

बुख़्ल की तालीम करते हो (चाहे जुबान से या इस तरह से कि इनको देख कर दूसरे यही तालीम पाते हैं) और वह इस चीज़ को पोशीदा रखते हों, जो अल्लाह तआला ने इनको अपने फज़्ल से दी है (इस से मुराद या माल व दौलत है जबकि बिना मसलहत हिफाज़त के सिर्फ बुख़्ल की वजह से छुपावे की अहले हुकूक़ इन से तवक्कों ही न करें, या मुराद इल्म दीन है कि यहूद अख़बार रिसालत को छुपाया करते थे, बस बुख्ल भी आम हो जावेगा बस इसमें बुख़्ल व मुन्करीन रिसालत दोनों आ गए) और हमने ऐसे ना सपाहों के लिए जो नेमत माल या नेमत बईश्त रसूल (सल्ल॰) की हक़ शनासी न करे। अहानात आमेज़ सज़ा तैयार कर रखी है और जो लोग कि अपने मालों को लोगों के दिखलाने के लिए खर्च करते हैं और अल्लाह तआला पर और आख़िरी दिन (यानि क़यामत के दिन) पर एतकाद नहीं रखते (इनकी भी यही हालत है कि अल्लाह तआला को इनसे मोहब्बत नहीं) और बात यह है कि शैतान जिसका मुसाहिब हो जैसा इन मजकूर लोगों का हुआ है तो वह इसका बुरा मसाहिब है कि ऐसा मशवरा देता है जिस में अंजाम कार सख़्त ज़रूरी हो। ❑❑

## शेष.... कोविड से जंग...

18 दिन पहले ही क़ानून के रूप में पारित किया है हालांकि बाइडेन का कहना है कि वह केवल शुरूआती भुगतान था। इसके साथ ही बाइडेन ने अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कई और बड़े उपायों का अगले महीने ऐलान करने का वादा किया है। बाइडेन का कहना है कि गंभीर मानवीय संकट साफतौर पर दिख रहा है और बर्बाद करने के लिए वक्त नहीं है। हमें काम करना है और तुरंत काम करना है। जो बाइडेन के राहत बिल के लिए पैसा कर्ज़ लेकर दिया जाएगा। महामारी का सामना करने के उपायों के कारण सरकार पर पहले से ही उपायों के कारण सरकार पर पहले से ही हज़ारों अरब डॉलर का कर्ज़ बढ़ चुका है। बाइडेन के सहयोगियों का कहना है कि अतिरिक्त ख़र्चो और कर्ज़ के ज़रिए वे अर्थव्यवस्था को गहरे दलदल में उतरने से बचा लेंगे। कर्ज़ पर ब्याज की दर कम है इसलिए इसका बोझ संभाला जा सकता है। बाइडेन लंबे समय से कहते आ रहे हैं कि अर्थव्यवस्था का उपचार बहुत जटिल रूप में कोरोना वायरस पर नियंत्रण से जुड़ा है। उनकी यह सोच अमेरिका के सबसे मज़बूत व्यापार संघ यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सोच से मेल खाती है जो पारंपरिक रूप से डेमोक्रेटिक पार्टी की विरोधी रही है। चैम्बर की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि हमारी अर्थव्यवस्था को बहाल करने से पहले हमें निश्चित रूप से कोविड को हटाना होगा और इसके लिए टीकाकरण के काम को बहुत तेज़ी से लागू करना होगा। चेम्बर ने बाइडेन के बयान का स्वागत किया है। ❑❑

## शेष.... कोविड से जंग...

भरने का काम सरकार को ही करना होगा। दरअसल सीरम इंस्टीटयूट और भारत बायोटेक दोनों की वैक्सीन को एक साथ आपातकालीन मंज़ूरी मिलने पर सवाल उठे थे कि भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के तीसरे चरण का परीक्षण अभी पूरा भी नहीं हुआ, फिर भी उसे कैसे मंज़ूरी दे दी गई। तब यह कहा गया कि इसे क्लीनिकल ट्रायल मोड के वैकल्पिक टीके के तौर पर मंज़ूरी दी गई है। इसका मतलब है कि आपात स्थिति में ही इसको इस्तेमाल करने की बात कही गई थी। वैक्सीन बनाने वाली दोनों कंपनियों सीरम इंस्टीटयूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला और भारत बायोटेक के चेयरमैन कृष्णा इल्ला के बीच वैक्सीन को मंज़ूरी मिलने के बाद विवाद भी सामने आया था। ❑❑

# उत्तराखंड में 'आप' के मंसूबे

दिल्ली चुनाव में बड़ी जीत दर्ज करने वाली आम आदमी पार्टी (आप) ने देवभूमि उत्तराखंड में भी सियासी दस्तक देकर हलचल मचा दी है। आप 2022 के विधानसभा चुनाव में राज्य की सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। आप नेताओं के उत्तराखंड में लगातार हो रहे दौरों में लोगों की बढ़ती भागीदारी ने सत्तारूढ़ भाजपा और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की पेशानी पर बल डाल दिए हैं। आप नेताओं ने तो भाजपा सरकार पर सीधा हमला शुरू कर दिया है। उत्तराखंड में 2022 के मार्च में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है। इस समय राज्य में विधानसभा की 70 सीटों में से 57 पर भाजपा 11 पर कांग्रेस और दो पर निर्दलीयों का कब्ज़ा है। माना जा रहा है कि 2022 का चुनाव भी भाजपा और कांग्रेस के बीच ही रहेगा। लेकिन कुछ माह पहले आप मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अचानक ऐलान कर दिया कि उनकी पार्टी 2022 में सभी 70 सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े करेगी।

हालांकि भाजपा और कांग्रेस ने केजरीवाल की इस घोषणा को तवज्जोह नहीं दी। लेकिन आप पार्टी ने अपना काम शुरू कर दिया है। दिल्ली के विधायक दिनेश मोहनिया को प्रदेश प्रभारी बनाकर उत्तराखंड भेज दिया गया है। मोहनिया ने प्रदेशभर में दौरे शुरू कर हर क्षेत्र में लोगों को पार्टी से जोड़ने का काम शुरू कर दिया है। उन्होंने कई बड़े चेहरों और पूर्व नौकरशाहों को पार्टी में शामिल किया है। आप पार्टी का सियासी कुनबा बढ़ा, तो दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसौदिया ने भी उत्तराखंड में दौरे शुरू कर दिए। इनकी सभाओं में भी भीड़ जुट रही है। मनीष के बाद पंजाब से आप पार्टी के सांसद भगवंत मान ने कुमाऊं में किसान न्याय यात्रा निकाली। जसपुर से खटीमा तक निकाली गई इस किसान न्याय यात्रा में ख़ासी भीड़ जुटी थी क्योंकि यह पूरा क्षेत्र किसान बाहुल्य है।

अहम बात यह है कि आप पार्टी के नेता अपनी सभाओं और मीडिया के सामने सूबे की भाजपा सरकार पर हमलावर हैं। लोगों को बताया जा रहा है कि विकास के के केजरीवाल मॉडल ने दिल्ली में स्कूल, बिजली, पानी और स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए गए काम मील के पत्थर हैं। पिछले दिनों देहरादून के दौरे पर आए आप पार्टी के नेता मनीष सिसौदिया ने कहा कि उत्तराखंड की त्रिवेन्द्र रावत सरकार जीरो वर्क गर्वमेंट है। यहां तक कि उन्होंने उत्तराखंड की रावत सरकार पर हमला करते हुए आमहित में किए गए कोई पांच काम गिनाने की चुनौती तक दे डाली। उत्तराखंड सरकार के प्रवक्ता और काबीना मंत्री सदन कौशिक ने इस चुनौती को स्वीकार किया ओर कहा कि सिसौदिया समय और तारीख तय कर लें। वे पांच नहीं पांच सौ काम गिनाने को तैयार हैं।

बहस यहीं नहीं रुकी, सिसौदिया ने भी समय, और स्थान और तारीख तय कर कौशिक को खत लिखकर खुली बहस का आमंत्रण दे डाला। सिसौदिया तो तय समय पर पहुंचे उन्होंने कौशिक का एक घंटे तक इंतज़ार भी किया लेकिन कौशिक मौक़े से नदारद रहे। सिसौदिया ने चुटकी लेते हुए कहा ''उत्तराखंड सरकार ने कुछ किया ही नहीं, तो मंत्री जी खुल बहस में आखिर क्या गिनाते।'' उधर काबीना मंत्री मदन कौशिक ने सिसौदिया को लिखा एक पत्र मीडिया में जारी किया। इसमें कौशिक ने लिखा है ''आपने कथित दिल्ली मॉडल को सामने रखते हुए उत्तराखंड मॉडल के साथ सार्वजनिक बहस का निमंत्रण दिया है। उत्तराखंड भाजपा और उत्तराखंड सरकार आपके इस निमंत्रण का स्वागत करती है। भाजपा का कोई भी कार्यकर्ता आपसे बहस कर सकता है।'' अपने खत में कौशिक ने आप नेताओं को होप सेलर और टूरिस्ट पॉलिटिशियन भी कहा। उन्होंने यह कहा कि अन्ना हजारे द्वारा खड़े किए गए भ्रष्टाचार विरोधी जिस आंदोलन से आम आदमी पार्टी का उदय हुआ आज आपकी पार्टी उन मूल्यों से बहुत दूर आ गई है। कौशिक ने दिल्ली की कई समस्याओं का ज़िक्र भी अपने खत में किया। प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता और विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने यहां तक कह दिया कि आप नेता उत्तराखंड में सैर सपाटे के लिए आते हैं ऐसे लोगों के लिए भाजपा सरकार के मंत्री और नेताओं के पास समय ही नहीं है।

आप नेता दीपक बाली ने कहा कि पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता से भाजपा बेचैन हो रही है। चार वर्ष में भाजपा सरकार ने उत्तराखंड में कोई काम नहीं किया। आप ने दिल्ली में जिस तरह से काम किया है, उसी तरह का काम यहां भी करने की बात पार्टी कर रही है। उत्तराखंड के लोग भाजपा और कांग्रेस से आजिज़ आ चुके हैं और बदलाव चाहते हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी के प्रति रुझान बढ़ रहा है। ❑❑

## मोदी शासन दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक को बर्बाद करने का एक सबकः- राहुल गांधी

देश की खस्ताहाल अर्थव्यवस्था को लेकर एक बार फिर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, मोदी जी का शासन दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक को बर्बाद करने का एक सबक है। राहुल गांधी ने इस ट्वीट में यह बताने की कोशिश की है कि मोदी सरकार के फैसलों ने कैसे देश की अर्थव्यवस्था को धरातल पर ला दिया है। लगातार राहुल गांधी देश की बिगड़ी अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरते रहे हैं। नोटबंदी, जीएसटी, देश में 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी और लॉकडाउन जैसे मुद्दों पर राहुल गांधी खुलकर बोलते रहे हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि मोदी सरकार के यह वो फैसले हैं, जिनकी वजह से भारत की अर्थव्यवस्था औंधे मुंह गिरी, बावजूद इसके सरकार ने हालात को सुधारने के लिए कोई बड़ा कदम नहीं उठाया। बुधावार को केरल में अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड के दौरे पर पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी ने देश को कमजोर किया है, नोटबंदी और जीएसटी लाकर अर्थव्यवस्था को भी बर्बाद किया। उन्होंने कहा कि आज भारत में बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा है। उन्होंने देश को बांटा है और यही वजह है कि चीन ने भारत की सीमा में घुसपैठ की है।

## शेष.... कोरोना वैक्सीन कितने वर्ष कारगर होगी

समेत दुनियाभर के देशों ने टीकाकरण को जरी झंडी दे दी है। वैश्विक स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि क्लीनिकल ट्रायल का पर्याप्त डेटा न होने के कारण वैक्सीन निर्माता अभी यह बताने की स्थिति में नहीं है कि वैक्सीन कितने लम्बे समय तक सुरक्षा देगी और क्या वैक्सीन डोज सिर्फ टीका लेने वाले में बीमारी को रोकेगी या संक्रमण रोकने में भी कारगर होगी। आगे चलकर वैज्ञानिक दो खुराक के बीच समय के अंतर को कम करने, डोज को अधिक करने, कई वैक्सीन को आपस में मिलाकर ज़्यादा असरदार वैक्सीन बनाने की संभावनाओं पर विचार करेंगे। हालांकि अमेरिकी एजेंसी के अनुसार, इसके लिए क्लीनिकल ट्रायल के ठोस साक्ष्यों की ज़रूरत होगी। जो लोग कोरोना से ऊबर भी चुके हैं, उन्हें भी यह टीका लेना चाहिए, क्योंकि यह उनमें मज़बूत इम्युनिटी पैदा करेगी। अभी कोरोना से स्वस्थ होने के बाद व्यक्ति के शरीर में अपने आप प्राकृतिक तरीके से एंटीबॉडी तो बनती है लेकिन यह एंटीबाडी कितने दिनों तक कायम रहेगी, यह पता नहीं है। कुछ अध्ययनों में कहा गया है कि यह 2 से 3 माह से 8 माह तक हो सकती हैं हर व्यक्ति में एंटीबॉडी का स्तर भी अलग-अलग होता है। ❑❑

**SHANTI MISSION** (HINDI WEEKLY) NEW DELHI Postal Registration No. DL(C)-01/1266/2021-23
Publishing Date : **24 Jan.2021** Posting Days : **MON. - TUE.** at **N.D.P.S.O.** New Delhi-110002 R.N.I. 57270/93

मंज़र पस-मंज़र — मीम.सीन.जीम

# भ्रष्टाचार की जड़ें, सड़क सुरक्षा अभियान

# ज़िन्दगी के लिए महाभियान

## भ्रष्टाचार की जड़ें

भ्रष्ट अधिकारियों पर सतत निगरानी और कार्रवाई के दावों के बावजूद सरकारी महकमों में भ्रष्टाचार किस क़दर हावी है, हाल की कुछ घटनाओं ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है। दो दिन पहले गुवाहाटी में रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी को एक करोड़ रुपए की घूस मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। इस अधिकारी ने एक निजी कंपनी को ठेका दिलवाने के एवज में यह रक़म मांगी थी। पिछले दिनों राजस्थान में दौसा जिले की एसडीएम और पुलिस अधीक्षक को लाखों रुपए की घूस लेने के मामले में पकड़ा गया। देश सेवा का संकल्प लेकर प्रशासनिक सेवा में आए इन अधिकारियों ने राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने के काम में लगी कंपनी से यह घूस ली थी। इसी माह राजस्थान में ही एक जिला कलक्टर और उनके निजी सचिव को मोटी घूस लेने के मामले में गिरफ्तार किया गया था। ये घटनाएं बताती हैं कि चाहे बड़े स्तर पर हो या फिर ज़िला, तहसील या पंचायत स्तर पर, भ्रष्टाचार से मुक्त प्रशासन की कल्पना नहीं की जा सकती। भले कोई राज्य कितने दावे क्यों न करे कि उसके यहां भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन है, लेकिन भ्रष्ट सरकारी कर्मचारी और अधिकारी जिस तरह से लूट खसोट मचा रहे हैं, वह सरकारों के भ्रष्टाचार मुक्त होने के दावों की पोल खोलने के लिए काफी है।

भारत के शासन-प्रशासन में भ्रष्टाचार का रोग जन्मजात है। पिछले तीन-चार दशकों में यह समस्या और विकट हुई है। आश्चर्य की बात तो यह है कि चुनावों में कोई भी राजनीतिक दल इसे मुद्दा बनाने से चूकता नहीं है और भ्रष्टाचार खत्म करने और साफ-सुथरा प्रशासन देने का वादा करता है, लेकिन सत्ता में आते ही यह वादा हवा हो जाता है। सरकारों और प्रशासन में हर स्तर भ्रष्टाचार पर जिस तेजी से बढ़ा है, उससे आमजन की मुश्किलें ज़्यादा बढ़ी हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया की रिपोर्ट बताती है कि पिछले वर्ष इक्यावन प्रतिशत लोगों को संपत्ति और भूमि संबंधी कामों के लिए घूस देनी पड़ी, बीस प्रतिशत लोगों को को पुलिस में पैसे खिलाने पड़े। इसी तरह नगर निगम, बिजली विभाग, जल विभाग, आरटीओ दफ्तर और अस्पताल ऐसे ठिकाने हैं, जिनसे आमजन का सीधा साबक़ा पड़ता है और जहां बिना घूस के काम कराना पास संभव नहीं है। भारत में केन्द्रीय जांच ब्यूरो, प्रवर्तन निदेशालय, राजस्व खुफिया निदेशालय सहित कई जांच एजेंसियां हैं जिन पर भ्रष्टाचार पर नकेल कसने की ज़िम्मेदारी है। हालांकि जांच एजेंसियां भी इस बीमारी से पूरी तरह मुक्त होंगी, कह पाना मुश्किल है। सीबीआइ को लेकर तो समय-समय पर सुप्रीम कोर्ट ने जो तल्ख टिप्पणियां की हैं, ये स्थिति की गंभीरता को बताने के लिए पर्याप्त है।

राज्यों में भी भ्रष्टाचार निरोधक विभाग और लोकायुक्त जैसी संस्थाएं हैं। फिर भी भ्रष्ट अधिकारियों के हौंसले बुलंद होना बताता है कि उनके आगे सरकारी तंत्र बौना पड़ चुका है इसकी वजह यह है कि भ्रष्टाचार के मामलों में त्वरित और ठोस कार्रवाई नहीं होती और ज़्यादातर मामलों में आरोपियों को बचाने में एक बड़ा तंत्र जुट जाता है। पकड़े गए अधिकारियों और कर्मचारियों को दिखावे के तौर पर निलंबित भले कर दिया जाए, लेकिन थोड़े समय बाद ही सब कुछ पहले की तरह हो जाता है। वर्ष 2019 में केन्द्र सरकार ने कर महकमों से जुड़े कई अफसरों के ख़िलाफ़ कड़ी कार्रवाई कर यह संकेत दिया था कि यह भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेगी। लेकिन भ्रष्टाचारियों से निपटने के लिए सख़्त क़ानूनों के उपयोग से भी ज़्यादा ज़रूरी है मज़बूत राजनीतिक इच्छाशक्ति का होना, जिसका अभा तंत्र के विकास को बढ़ावा देता है।

## सड़क सुरक्षा अभियान

सड़क सुरक्षा माह के उद्घाटन कार्यक्रम में केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की ओर से दी गई यह जानकारी हतप्रभ करने वाली है कि देश में प्रतिदिन करीब 415 लोग सड़क दुर्घटनाओं में जान गंवाते हैं। कोई भी अनुमान लगा सकता है कि एक वर्ष में यह संख्या कहां तक पहुंच जाती होगी? इसका कोई मतलब नहीं कि प्रतिवर्ष लगभग डेढ़ लाख लोग सड़क हादसों में जान से हाथ धो बैठे। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय लोगों के सहयोग से वर्ष 2025 तक सड़क हादसों में 50 प्रतिशत की कमी लाना चाहता है, लेकिन यह काम केवल सड़क सुरक्षा माह के माध्यम से लोगों को जागरुक करने भर से होने वाला नहीं है। सड़क हादसों के प्रति लोगों को सजग करने का अपना एक महत्व है, लेकिन बात तो तब बनेगी जब मार्ग दुर्घटनाओं के मूल कारणों का निवारण करने के लिए ठोस क़दम भी उठाए जाएंगे। कुशल ड्राइवरों की कमी को देखते हुए ग्रामीण एवं पिछड़े इलाकों में ड्राइवर ट्रैनिंग स्कूल खोलने की तैयारी सही दिशा में उठाया गया क़दम है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ करना होगा।

**सबसे पहले तो सड़कों के किनारे अतिक्रमण को प्राथमिकता के आधार पर दूर करना होगा। यह सड़क हादसों का कारण बनता है, ख़ासकर तब जब ऐसे ठिकानों पर बस, ट्रक और अन्य वाहन खड़े कर दिए जाते हैं। यह ठीक नहीं कि ढाबे भारी वाहनों के लिए पार्किंग स्थल बन पाएं। सड़क किनारे बसे गांवों से होने वाला हर तरह का बेरोक-टोक आवागमन भी जोखिम बढ़ाने का काम करता है।**

सबसे पहले तो सड़कों के किनारे अतिक्रमण को प्राथमिकता के आधार पर दूर करना होगा। यह अतिक्रमण सड़क हादसों का कारण बनता है, ख़ासकर तब और जब ऐसे ठिकानों पर बस, ट्रक और अन्य वाहन खड़े कर दिए जाते हैं। यह ठीक नहीं कि ढाबे भारी वाहनों के लिए पार्किंग स्थल बन पाएं। यह भी समझने की ज़रूरत है कि सड़क किनारे बसे गांवों से होने वाला हर तरह का बेरोक-टोक आवागमन भी जोखिम बढ़ाने का काम करता है। इस स्थिति से हर कोई परिचित है, लेकिन ऐसे उपाय नहीं किए जा रहे, जिससे कम से कम राजमार्ग तो अतिक्रमण और बेतरतीब यातायात से बचे रहें। इसमें संदेह है कि उल्टी दिशा में वाहन चलाने, लेन की परवाह न करने और मनचाहे तरीके से ओवरटेक करने जैसी समस्याओं का समाधान केवल जागरुकता अभियान चलाकर किया जा सकता है। इन समस्याओं का समाधान तो तब होगा जब सुगम यातायात के लिए चौकसी बढ़ाई जाएगी और लापरवाही का परिचय देने अथवा जोखिम मोल लेने वालों के ख़िलाफ़ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह ठीक नहीं कि जानलेवा सड़क दुर्घटनाओं का सिलसिला क़ायम रहने के बाद भी राजमार्गों पर सीसीटीवी और पुलिस की प्रभावी उपस्थिति नहीं दिखती। कुछ राज्य सरकारों ने सड़क हादसों को रोकने के लिए राजमार्ग पुलिस की व्यवस्था अवश्य कर रखी है, लेकिन वह या तो संख्याबल के अभाव से जूझती है अथवा अन्य ज़िम्मेदारियों का निर्वाह करती दिखती हैं। अच्छा होगा कि राज्य सरकारें यह समझें कि सड़क हादसों को रोकना उनकी भी ज़िम्मेदारी है

## ज़िन्दगी के लिए महाभियान

16 जनवरी 2021, भारत में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू हुआ। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बड़े भावुक अंदाज़ में टीकाकरण अभियान शुरू करने का ऐलान करते हुए उन स्वास्थ्य कर्मियों को याद किया जो संक्रमण के कारण असमय दुनिया से चले गए। वाक़ई जिन लोगों ने निस्वार्थ भाव से, अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों की सेवा की, उनके प्रति जितनी कृतज्ञता दिखाई जाए, वो कम है। काश मोदी जी कुछ भावुकता उन लोगों के लिए प्रदर्शित करते जो लॉकडाउन जैसे अविचारित फैसलों के कारण अपनी जान जोखिम में डालकर घर लौटने को मजबूर हुए और अब भी जिनका जीवन सामान्य अवस्था में नहीं लौट पाया है। इनमें से बहुतेरे लोगों को वो वोट के बदले फ्री वैक्सीन का वादा भी किया गया। हालांकि तब तक तय नहीं था कि वैक्सीन कब जाएगी। लेकन अब एक नहीं दो-दो वैक्सीन आ चुकी है और उनके लगने की शुरुआत भी हो गई हे। सरकार ने पहले स्वास्थ्यकर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगाने का निश्चय किया है और देशभर के अनेक अस्पतालों में यह टीकाकरण चल पड़ा है। सरकार ने पहले दिन 3 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा था। लेकिन वैक्सीन की गुणवत्ता, साइड इफेक्टस आदि के कारण इस लक्ष्य से काफी कम लोगों को वैक्सीन लगे। पहले दिन 1 लाख 91 हजार लोगों ने टीका लगवाया। इसमें दिल्ली एम्स के निर्देशक रणदीप गुलेरिया भी शामिल रहे। हालांकि वैक्सीन को लेकर अब भी प्रश्न उठ रहे हैं। दिल्ली के आरएमएल अस्पताल के कई डॉक्टरों ने वैक्सीन लगवाने से इंकार कर दिया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील करते हुए वैक्सीन को पूरी तरह सुरक्षित बताया है। लेकिन उनकी यह अपील और कारगर साबित होती अगर वे खुद वैक्सीन लगवाने की पहल करते। मोदी जी जो बाइडेन से प्रेरित होकर इसका लाइव प्रसारण करवाते तो उनके प्रशंसक उनके और ज़्यादा मुरीद हो जाते। कई विपक्षी नेताओं ने भी ऐसी ही मांग की है। इससे उन्हें भी करारा जवाब मिल जाता। लेकिन शायदसरकार लखनवी तहज़ीब में जनता से पहले आप का निवेदन कर रही है। जनता को कोरोना से जितनी जल्दी सुरक्षा मिले, उतना अच्छा। लेकिन अगर इस सुरक्षा की ढाल में संदेह के छेद हो, तो उन्हें

बाक़ी पेज 11 पर

**ज़रूरी ऐलान**

आपकी ख़रीदारी अवधि पते की चिट पर अंकित है। अवधि की समाप्ति से पूर्व रक़म भेजने की कृपा करें।

**रक़म भेजने के तरीक़े:-**

❶ मनीआर्डर द्वारा ❷ **Paytm** या **PhonePe** द्वारा **9811198820** पर
**SHANTI MISSION**
❸ ऑनलाइन हेतु बैंक खाते का विवरण
**SBI** A/c **10310541455**
Branch: **Indraprastha Estate**
IFS Code: **SBIN0001187**

**ख़रीदारी चन्दा**

| | |
|---|---|
| वार्षिक | Rs.130/- |
| 6 महीने के लिए | Rs.70/- |
| एक प्रति | Rs.3/- |

जानकारी के लिये सम्पर्क करें
साप्ताहिक
**शांति मिशन**
1, बहादुरशाह ज़फर मार्ग,
नई दिल्ली-110002
फोन : 011-23311455

अपने प्रिय अख़बार साप्ताहिक शांति मिशन को इंटरनेट पर देखने के लिये लॉगऑन करें:
**www.aljamiat.in ——— Mob. 9811198820**
**E-mail: Shantimissionweekly@gmail.com**

जमीअत ट्रस्ट सोसायटी की तरफ से मुद्रक, प्रकाशक शकील अहमद सैयद ने शेरवानी आर्ट प्रिंटर्स, 1480, क़ासिमजान स्ट्रीट, बल्लीमारान, दिल्ली-6 से छपवाकर मदनी हाल, न. 1, बहादुर शाह ज़फ़र मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित किया। संपादक:- मोहम्मद सालिम, फोन:- 23311455, 23317729, फैक्स:- 23316173